@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'पश्चिम बंगाल की तानाशाही सरकार को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब'

वर्ष-16, अंक-02 16-31 जनवरी, 2021 (पाक्षिक) ₹20

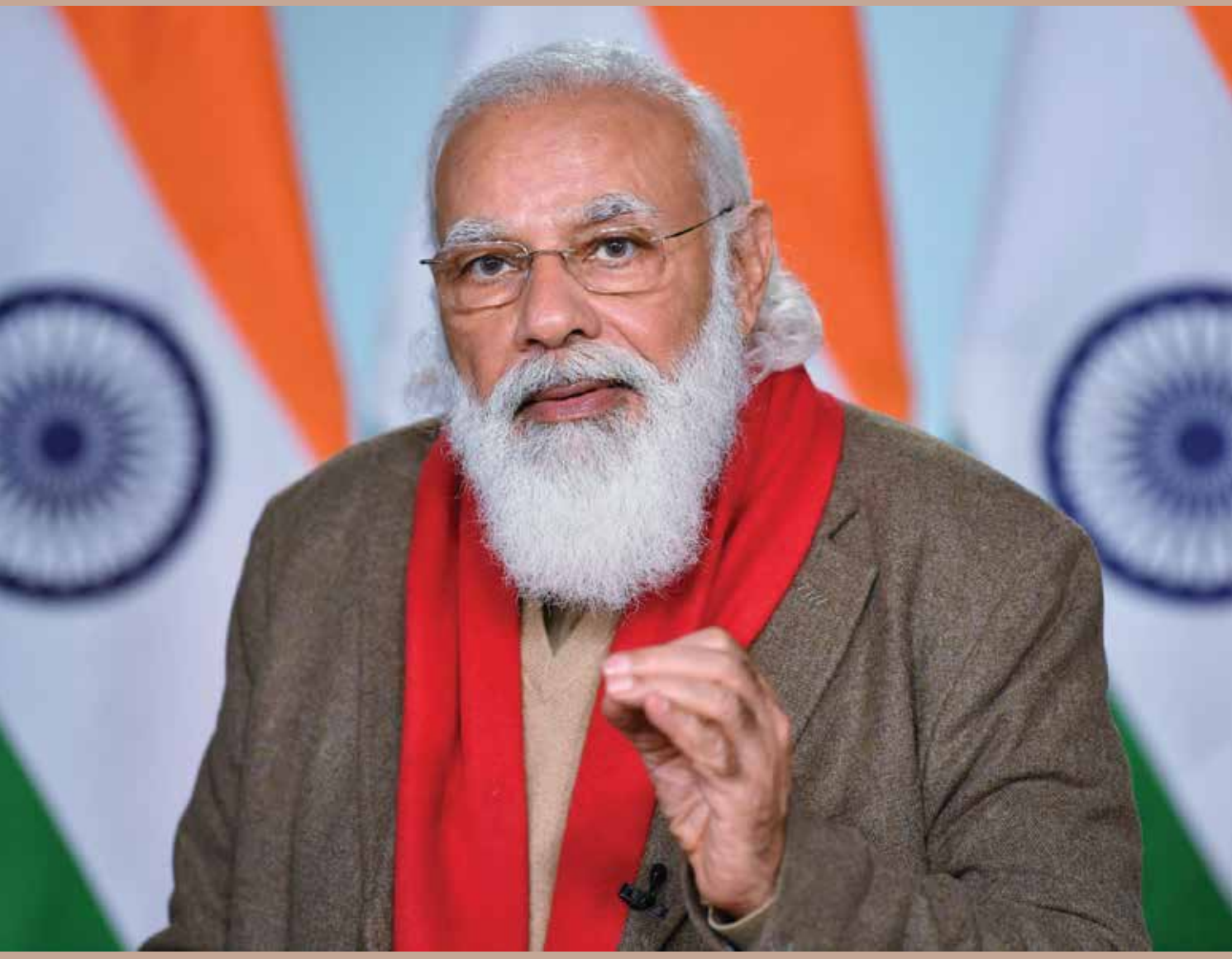

'मेड इन इंडिया' वैक्सीन से बनेगा कोविड मुक्त राष्ट्र

पश्चिम बंगाल में घर-घर जाकर 'एक मुट्ठी चावल संग्रह' के राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बर्धमान (पश्चिम बंगाल) स्थित जगदानंदपुर गांव में एक किसान परिवार के घर भोजन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

गुजरात भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) पर दिल्ली के द्वारका-नजफगढ़ में किसानों को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

महरौली (दिल्ली) में एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है कोविड वैक्सीनेशनः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस नए साल में कोविड के उपचार के लिए दो 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन का सफल विकास करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव...

09 पश्चिम बंगाल की तानाशाही सरकार को जनता देगी मुंहतोड़ जवाबः नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'कृषक सुरक्षा' ग्राम सभा में अपने संबोधन...

11 भारत के लोगों को भाजपा नेतृत्व पर पूरा भरोसा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने 3 जनवरी 2021 को...

18 सरकार का लक्ष्य कृषि लागत घटाना व किसानों को मिले सही मूल्यः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान...

22 असम की संस्कृति देश का गहना हैः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 26 दिसंबर को असम में अनेक विकास परियोजनाओं...

वैचारिकी

अपनी विचारधारा सहयोग पर आधारित / दीनदयाल उपाध्याय 15

श्रद्धांजलि

विजया राजे सिंधियाः त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति 17

मन की बात

भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल का लें संकल्पः नरेन्द्र मोदी 33

अन्य

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी-मदार खंड और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू खुर्जा-न्यू भाऊपुर खंड देश को समर्पित 12

अनाजों, गन्ना, चुकन्दर आदि से इथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने हेतु एक योजना को मिली मंजूरी 14

जयराम ठाकुर सरकार ने तीन वर्षों में विकास की नई गाथा लिखीः जगत प्रकाश नड्डा 20

'अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मील का पत्थर' 24

जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत की शुरुआत 27

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल, जहां मेट्रो रेल बिना ड्राइवर के चलती हैः नरेन्द्र मोदी 29

किसानों की आय बढ़ाने में 'किसान रेल सेवा' एक बड़ा कदमः नरेन्द्र मोदी 30

सरकार ने सभी फसलों के लिए 40-70 प्रतिशत तक बढ़ाई एमएसपी 31

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

यह गर्व की बात है कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वे दोनों 'मेड इन इंडिया' हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। वह आत्मनिर्भर भारत, जिसका आधार है– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

जगत प्रकाश नड्डा

आजादी के बाद 75 वर्षों तक जहां जम्मू-कश्मीर में विकास नदारद था, वहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण विकास के मार्ग खुल रहे हैं। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 28,400 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना से नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

अमित शाह

मोदीजी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से दूर कर वहां विकासवाद की शुरुआत की है। कैबिनेट द्वारा जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का निर्णय मोदीजी के हृदय में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थान को दर्शाता है।

राजनाथ सिंह

अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कही भी, जहां उसे बेहतर कीमत मिले, अपनी फसल बेचने के लिए आजाद होगा।

बी. एल. संतोष

वायरस से वैक्सीन तक यह एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और समाज ने डटकर मुकाबला किया। हम मिलकर चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम थे।

नितिन गडकरी

केवीआईसी के माध्यम से गाय के गोबर से बने 'प्राकृतिक पेंट' ईको फ्रेंडली, नॉन टौक्सिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल है और भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित है। इससे पशुधन रखने वाले किसानों को साल में 55 हजार रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी होगी।

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

'मेड इन इंडिया' कोविड टीके 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रतीक

भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा भारत में निर्मित दो टीकों को स्वीकृति मिलने के साथ ही कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई में देश एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारत के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि एक नहीं बल्कि दो टीके देश में चलाए जाने वाले व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए अब तैयार हैं। सीरम इंस्ट्रीयूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित 'कोविशील्ड' एवं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित 'कोवैक्सीन' यह प्रमाणित करता है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य किया जाए तब किसी भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक ओर जहां विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादक सीरम इंस्ट्रीयूट ऑफ इंडिया ने 'एस्ट्राजेनेका' के साथ मिलकर कोविशील्ड का निर्माण किया, वहीं दूसरी ओर भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर 'कोवैक्सीन' को विकसित किया है। 'मेड इन इंडिया' टीकों के निर्माण के लिए भारत अपने वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं पर गर्व कर रहा है। इस विलक्षण उपलब्धि से कोरोना महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई मजबूत हूई है तथा इससे आने वाले दिनों में कोविड-मुक्त विश्व का मार्ग प्रशस्त होगा।

जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र ने कोविड महामारी के विरुद्ध संघर्ष किया है, उस पर हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे देश ने न केवल हर चुनौती का मजबूती से सामना किया, बल्कि अन्य देशों की भी सहायता में तत्पर रहा। यदि पीछे मुड़कर कोविड महामारी के शुरुआती दिनों पर नजर डाली जाए तो मास्क और सैनिटाइजर बनाने की देश की क्षमता पर भी कुछ लोग प्रश्न खड़ा करके भय का वातावरण बनाना चाह रहे थे, परन्तु आज देश ने टीके का निर्माण कर न केवल उनके मुंह पर ताला लगा दिया है, बल्कि पीपीई किट, मास्क, चिकित्सकीय उपकरण और यहां तक कि दवाइयों का निर्यात भी अन्य देशों को किया जा रहा है। महामारी की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए देश में सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं विकसित तो हुईं ही, साथ ही 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर, आक्सीजन बेड, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य चिकित्सकीय उपकरणों के साथ-साथ व्यापक जन-जागरण अभियान भी देश के कोने-कोने में सफलतापूर्वक चलाया गया। इन महत्वपूर्ण कार्यों के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति तक राशन एवं अन्य राहत सामग्री पहुंचाते हुए 80 करोड़ लोगों को सीधा लाभ देते हुए पूरे देश के लिए भारी राहत पैकेज को भी जमीन पर क्रियान्वित किया गया। इस संकट काल में अर्थव्यवस्था को विभिन्न पहलों द्वारा मजबूत रखते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के माध्यम से कोविड के बाद के विश्व के लिए भी देश को पूरी तरह से तैयार किया गया है। इन सभी कदमों का सकारात्मक परिणाम सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है जबकि अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज विश्व पटल पर अपनी दस्तक दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के दिशा-निर्देशों में जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में राहत कार्य चलाया, वह पूरे विश्व के लिए एक अनुपम उदाहरण है। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि किस प्रकार एक राजनैतिक दल के समर्पित कार्यकर्ता करोड़ों लोगों की संकट काल में सेवा कर एकता एवं एकजुटता का संदेश समाज को दे सकते हैं।

कोविड महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करने के भारत के संकल्प को 'मेड इन इंडिया' कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन के निर्माण के रूप देखा जा सकता है, जो भारतीय वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं का पूरी मानवता के लिए उपहार है

कोविड महामारी के ऊपर विजय प्राप्त करने के भारत के संकल्प को 'मेड इन इंडिया' कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन के निर्माण के रूप देखा जा सकता है, जो भारतीय वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं का पूरी मानवता के लिए उपहार है। पूरे राष्ट्र को अपने चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, लैब तकनीशियनों एवं कोरोना योद्धाओं पर गर्व है जो महामारी के काल में अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों की अथक सेवा कर रहे हैं। एक ओर जहां कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल लगातार देश की क्षमता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देश में भय और निराशा का वातावरण बनाने में लगे रहे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं संकल्पित नेतृत्व में पूरे राष्ट्र ने एकजुट रहकर इस लंबे संक्रमण काल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियों अर्जित किया। इस पूरे काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अथक कार्यों से देश का मनोबल निरंतर ऊंचा रखा तथा अब जबकि लगातार घटते हुए कोरोना संक्रमण का समाचार प्राप्त हो रहा है, पूरे राष्ट्र का आत्मविश्वास कई गुना और भी अधिक बढ़ गया है। आज जबकि पूरा देश एक स्वस्थ एवं कोविड मुक्त भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, 'मेड इन इंडिया' कोविड टीके 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रतीक के रूप में उभरे हैं जो समस्त मानवता के कल्याण हेतु समर्पित है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है कोविड वैक्सीनेशनः नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रीय नियामक द्वारा दो टीकों (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) के लिए आपात उपयोग की अनुमति या त्वरित अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो रोग से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को मजूबती देगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस नए साल में कोविड के उपचार के लिए दो 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन का सफल विकास करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर 4 जनवरी को श्री मोदी ने कहा कि भारत का कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।

उन्होंने सीएसआईआर समेत देश के सभी वैज्ञानिक संस्थानों की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने देश के समक्ष पेश हर चुनौती का समाधान तलाशने के लिए मिल जुलकर काम किया।

प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 9 जनवरी को एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

श्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर कहते हुए कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। राष्ट्रीय नियामक द्वारा दो टीकों (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) के लिए आपात उपयोग की अनुमति या त्वरित अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि रोग से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को मजूबती देगा।

प्रधानमंत्री जी को निकट भविष्य में टीकाकरण आरम्भ करने के लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर केंद्र की तैयारी की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया गया। टीकाकरण अभियान जनभागीदारी; चुनावों (मतदान केन्द्र रणनीति) और सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के अनुभव के उपयोग; वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ बिना किसी समझौते; वैज्ञानिक और नियामकीय मानदंडों, अन्य एसओपी पर बिना कोई समझौता किए; तथा प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यवस्थित और सुचारु कार्यान्वयन के सिद्धांतों पर आधारित है।

कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, जिसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा सह-रुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु के जनसंख्या समूहों, जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री को को-विन टीका प्रदायगी प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया। यह अनूठा डिजिटल प्लेटफॉर्म टीके के स्टॉक, उनके भंडारण का तापमान और कोविड-19 टीका के लाभार्थियों की वैयक्तिक ट्रैकिंग की वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफॉर्म पूर्व-पंजीकृत लाभार्थियों, उनके सत्यापन और टीका अनुसूची के सफल समापन पर एक डिजिटल प्रमाण पत्र जेनरेट करने के लिए ऑटोमेटेड सत्र आवंटन के जरिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 79 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत कर लिए गए हैं।

चूंकि टीकाकरण अभियान में टीका लगाने वालों तथा टीका प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के दौरान 2,360 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी, कोल्ड चेन अधिकारी, आईईसी अधिकारी, विकास भागीदार आदि सम्मिलित थे। राज्यों, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षणों के एक हिस्से के रूप में अभी तक

भारत में कोविड-19 टीके को मंजूरी मिलने का डब्ल्यूएचओ ने किया स्वागत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 के टीके के आपात उपयोग की मंजूरी देने के भारत के फैसले का स्वागत करते हुए 3 जनवरी को कहा कि यह मौजूदा महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज और मजबूत करने में मदद करेगा। डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड-19 के टीके के प्रथम आपात उपयोग की मंजूरी का विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वागत करता है। भारत द्वारा आज लिए गये फैसले से क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने और उसे मजबूत करने में मदद मिलेगी।

61,000 से अधिक कार्यक्रम प्रबंधकों, 2 लाख टीका लगाने वालों और टीकाकरण टीम के अन्य 3.7 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री जी को देश भर में तीन चरणों में संचालित किए गए पूर्व परीक्षण (ड्राई रन) से भी अवगत कराया गया। तीसरा ड्राइ रन कल 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 4895 सत्रों को कवर करते हुए 615 जिलों में संचालित किया गया।

विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू आदि सहित आगामी त्यौहारों को देखते हुए कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 से आरम्भ होगा।

भारत में सीरम इंस्ट्रीयूट और भारत बायोटेक के कोविड-19 टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी

मैसर्स सीरम और मैसर्स भारत बायोटेक के टीकों की दो खुराक दी जानी है। टीकों को 2 से 8 डिग्री सेंटिग्रेट पर स्टोर किया जाना है

भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके 'कोविशील्ड' और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके 'कोवैक्सीन' के देश में सीमित आपात इस्तेमाल को तीन जनवरी को मंजूरी दे दी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की अनुशंसा के आधार पर भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने यह मंजूरी प्रदान की।

भारत के औषधि महानियंत्रक के प्रेस वक्तव्य के अनुसार केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक 1 और 2 जनवरी, 2021 को हुई और मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मैसर्स भारत बायोटेक के कोविड-19 वायरस के टीके के सीमित आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति के प्रस्ताव और मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल से संबंधित सिफारिशें की गईं। विषय विशेषज्ञ समिति में पल्मोनोलॉजी, इम्युनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉर्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे ने एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से तकनीकी हस्तांतरण के साथ सार्स-कोव-2 स्पाइक (एस) ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर एक रीकॉम्बिनेंट चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन (कोविशील्ड) तैयार की है। फर्म ने 18 साल या उससे अधिक आयु के 23,745 प्रतिभागियों पर विदेशी अध्ययनों से मिले सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभाव से संबंधित डेटा को प्रस्तुत किया। टीके की क्षमता 70.42 प्रतिशत प्रभावी पाई गई। इसके बाद मैसर्स सीरम को देश में 1600 प्रतिभागियों पर दूसरे और तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति प्रदान की गई। फर्म ने परीक्षण से मिले अंतरिम सुरक्षा और प्रतिरक्षा पैदा होने संबंधी डेटा को प्रस्तुत किया और इस डेटा को विदेशी अध्ययनों से मिले डेटा के समान पाया गया। हमारी विषय विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ आपातकालीन स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है।

प्रेस वक्तव्य के अनुसार मैसर्स भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी (पुणे), जहां से उन्हें वायरस सीड स्ट्रेन्स मिले, के सहयोग से एक पूर्ण विरिअन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन (कोवैक्सीन) विकसित की है। यह टीका वेरो सेल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसका सुरक्षा और प्रभावकारिता को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि फर्म ने जानवरों की विभिन्न प्रजातियों जैसे चूहे, खरगोशों, सीरियन हम्सटर में सुरक्षा और प्रतिरक्षा पैदा होने संबंधी डेटा जुटाए और बंदरों (रीसस मैकाक) और हम्सटरों पर चैलेंज स्टडीज कार्य किया गया। पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल करीब 800 सब्जेक्ट्स में किए गए और परिणामों से पता चला कि टीका सुरक्षित है और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तीसरे चरण का परीक्षण भारत में 25,800 वालंटियरों पर शुरू किया गया और अब तक 22,500 प्रतिभागियों को देशभर में टीका लगाया गया है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टीका सुरक्षित पाया गया है।

प्रेस वक्तव्य के अनुसार विषय विशेषज्ञ समिति ने टीके की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को लेकर डेटा की समीक्षा की है और जनहित में आपातस्थिति में क्लीनिकल ट्रायल मोड में सीमित इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की है। क्लीनिकल ट्रायल मोड में टीकाकरण, खासतौर से म्यूटेंट स्ट्रेन्स द्वारा संक्रमण के मामले में और अधिक विकल्प हैं। फर्म द्वारा देश के भीतर चल रहे क्लीनिकल ट्रायल जारी रहेंगे।

प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने डीएनए प्लेटफॉर्म तकनीक का इस्तेमाल कर एक नोवेल कोरोना

वायरस-2019-एनकोव-वैक्सीन तैयार की है। फर्म ने 1000 से अधिक प्रतिभागियों पर पहले और दूसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया, जो चल रहा है। अंतरिम आंकड़ों से पता चलता है कि इंजेक्शन से तीन खुराक के साथ टीका सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक है। इसके बाद फर्म ने 26 हजार भारतीय प्रतिभागियों में तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी है, जिसकी सिफारिश विषय विशेषज्ञ समिति ने कर दी है। मैसर्स सीरम और मैसर्स भारत बायोटेक के टीकों की दो खुराक दी जानी है। तीनों टीकों को 2 से 8 डिग्री सेंटिग्रेट पर स्टोर किया जाना है।

प्रेस वक्तव्य के अनुसार समीक्षा के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा निर्णय लिया गया है और उसके अनुसार, हम आपातस्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मैसर्स सीरम और मैसर्स भारत बायोटेक के टीकों को मंजूरी देने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर को तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल के लिए अनुमति दी जा रही है।

'टीकों को डीसीजीआई की मंजूरी से कोविड मुक्त भारत की मुहिम को मिलेगा बल'

भारत में कोविड-19 रोधी दो टीकों के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत की जंग में निर्णायक क्षण बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन जनवरी को कहा कि इससे कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में जिन दो टीकों के आपात इस्तेमाल की स्वीकृति दी गई है, वे भारत निर्मित हैं। उन्होंने देश को, वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों को बधाई देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। वह आत्मनिर्भर भारत, जिसका आधार है– सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।

उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों और सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे।

श्री मोदी ने ट्वीट किया कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण! सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने से स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। ■

टीकों की मंजूरी मिलना निर्णायक व ऐतिहासिक क्षणः जगत प्रकाश नड्डा

कोविड रोधी दो टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि कोविड से बचाव के लिए दो स्वदेशी टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीजीसीआई की मंजूरी मिलना देश के स्वास्थ्य जगत के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आज एक नया आयाम स्थापित किया है। सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को बहुत बधाई।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अद्भुत कार्य हो रहे हैं, वो चिरस्मरणीय रहेंगे। भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र मे बदल गया है। मोदी जी ने देश के हर वर्ग को एक साथ लाकर कोविड से लड़ाई के लिए तैयार किया। दिन-रात जनसेवा के कार्य को समर्पित डॉक्टर्स, पुलिस और सफाईकर्मियों को नमन।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धिः अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 3 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटैक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी।

अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री शाह ने कहा कि भारत के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी वैज्ञानिकों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत को कोविड मुक्त बनाने के प्रयास के लिए शुभकामनाएं।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमने हर बार यह देखा है कि न्यू इंडिया संकट के समय मानवता की भलाई और नवाचार के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने में गेम चैंजर साबित होगी।

श्री शाह ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय मे पूरी निष्ठा के साथ मानवता की सेवा करने वाले हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ़, सुरक्षाकर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं। राष्ट्र मानवता की निःस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा।

पश्चिम बंगाल की तानाशाही सरकार को जनता देगी मुंहतोड़ जवाबः जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 9 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में जगदानंदपुर (कटवा) के ग्राम मैदान में 'कृषक सुरक्षा' ग्राम सभा को संबोधित कर राज्य भर में भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किये जाने वाले 40,000 सभाओं की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के पश्चात् उन्होंने जगदानंदपुर गांव में घर-घर जाकर 'एक मुट्ठी चावल संग्रह' अभियान का शुभारंभ किया। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी राज्य के सभी 73 लाख किसानों के घर-घर पहुंचेगी और उनसे 'एक मुट्ठी चावल' का संग्रह करेगी। श्री नड्डा ने इस अभियान का शुभारंभ करने के पश्चात् जगदानंदपुर गांव में ही एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन किया। इससे पहले बर्धमान के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उतरने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्री नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले कटवा के पास प्रसिद्ध श्री राधा गोबिंद मंदिर में पूजा-अर्चना की और पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारतवर्ष की मंगलकामना का आशीर्वाद प्राप्त किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'कृषक सुरक्षा' ग्राम सभा में अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि जिस धरा से स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सन्मार्ग की राह दिखाई, जहां गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने कृतित्व से समाज और देश को नई दिशा दिखलाई, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई, जहां महर्षि अरविंदो घोष ने अध्यात्म को एक नई उंचाई पर पहुंचाया और जहां हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की मिट्टी की सुगंध से सुवासित भारत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी और 'एक विधान, एक प्रधान और एक निशान' का मंत्र दिया था, मैं ऐसी महान भूमि को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि आज मैंने यहां के पुरातन श्री राधा गोविंद मंदिर में प्रभु के दर्शन किये। ये वही मंदिर है जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। मैं भगवान् श्री राधा गोविंद को नमन करता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि आज जिस तरह से जन-सैलाब ने भाजपा के राज्यव्यापी अभियान 'एक मुट्ठी चावल संग्रह' को अपना समर्थन दिया है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की सरकार का जाना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना तय है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम पश्चिम बंगाल को विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हुए यहां की जनता की भलाई सुनिश्चित करें।

श्री नड्डा ने कहा कि आज मैंने जगदानंदपुर गांव से 'कृषक सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की है। मैंने आज यहां के किसानों से 'एक मुट्ठी चावल' का दान लिया है। आज से लेकर 24 जनवरी, 2020 तक हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से मिलेंगे, उनसे 'एक मुट्ठी चावल' का दान ग्रहण करेंगे और दुर्गा मां की सौगंध खायेंगे कि किसानों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। राज्य में हमारी सरकार आने पर पश्चिम बंगाल के किसानों को उनका हक़ दिलाया जाएगा जिससे तृणमूल की ममता सरकार ने वंचित कर रखा है। 27 से 31 जनवरी तक हम पश्चिम बंगाल के गांव-गांव

में 'कृषक भोज' आयोजित करेंगे और यह तय करेंगे कि जिस तरीके से राज्य में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और जो भी किसानों के साथ अन्याय कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और किसानों को इसके माध्यम से एकजुट भी करेंगे। इस तरह पार्टी कार्यकर्ता राज्य के 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों के साथ संवाद करेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि दो साल बाद अब जाकर आज मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि हम 'प्रधानमंत्री सम्मान निधि' योजना से जुड़ना चाहते हैं। ममता दीदी, अब जब हम 'कृषक सुरक्षा' अभियान शुरू कर चुके हैं, तो आपकी जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम इस योजना को यहां पर भी लागू कर दिखाएंगे। हम दो वर्षों से बोलते रहे कि पश्चिम बंगाल के किसानों को भी 'प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि' योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन तब तो ममता दीदी, आपने नहीं सुनी। आज भी बंगाल के लगभग 70 लाख किसान इससे वंचित है। पश्चिम बंगाल के 23 लाख

लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर इस योजना के लिए जुड़ने की इच्छा जताई है लेकिन ममता दीदी ने किसानों की सूची को ही फाइनल नहीं किया। जब ममता दीदी को अपने पैरों के नीचे से पश्चिम बंगाल की जमीन खिसकती दिखाई दी, तब जाकर उन्हें किसानों की याद आई है। अब पछताए होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत! ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को लाना है।

उन्होंने कहा कि ई-नाम से पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। आज पश्चिम बंगाल के लाखों किसान स्वायल हेल्ड कार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने सौ किसान रेल की शुरुआत की है। अभी 28 दिसंबर, 2020 को ही प्रधानमंत्री जी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई जो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के जो तीन विधेयक संसद से पारित कराये हैं, वे न केवल देश के किसानों को फसल बेचने की आजादी देते हैं, बल्कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी देने वाले हैं। अब किसान अपनी जमीन पर होने वाली उपज का सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।

• पहले ममता दीदी 'मां, माटी और मानुष' का नारा देती थी लेकिन अब उनकी सरकार तानाशाही, तुष्टिकरण और तोलाबाजी की सरकार हो गई है।

श्री नड्डा ने कहा कि किसानों की औसत मासिक आय के हिसाब से पश्चिम बंगाल 29 राज्यों में 24वें स्थान पर आता है। हमें यह स्थिति बदलनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की कई योजनाओं ने देश की तस्वीर बदली है चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, जन-धन हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रखा है, जबकि देश के लगभग 50 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8,575 करोड़ रुपये की लागत से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 3665 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पश्चिम बंगाल में हुआ है।

ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार चावल चोर, तिरपाल चोर, राशन चोर, कोयला चोर और बालू चोर सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट का मुकाबला करने के लिए पश्चिम बंगाल की गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन दिया लेकिन राशन की बोरियां मिली टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से। टीएमसी मतलब कट मनी, टीएमसी मतलब चावल चोर, टीएमसी मतलब तिरपाल चोर। जब अम्फान रिलीफ का पैसा जनता तक नहीं पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि तीन महीने के अंदर-अंदर सीएजी (CAG) इसका ऑडिट कर जवाब दे कि आखिर ये पैसा गया कहां? लेकिन ममता दीदी चोर को बचाने सुप्रीम कोर्ट चली गई।

श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के निवासियों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी जी ने इसे 'कोरोना कैरियर' कहा था। ये है इनका पश्चिम बंगाल की जनता के लिए प्यार! उन्होंने कहा कि पहले ममता दीदी 'मां, माटी और मानुष' का नारा देती थी लेकिन अब उनकी सरकार तानाशाही, तुष्टिकरण और तोलाबाजी की सरकार हो गई है। अब तो पश्चिम बंगाल की हालत यह हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार की ऐसी भयावह स्थिति हो गई है पश्चिम बंगाल में। चिट फंड, नारदा, सारदा जैसे कई घोटाले इसके उदाहरण है। आजकल पश्चिम बंगाल में एक नए राजकुमार की चर्चा हो रही है। किस तरीके से धन का उपार्जन उसने किया है, यह पश्चिम बंगाल की जनता जानती है लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं तक नहीं चलने वाला। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी धरती पर पश्चिम बंगाल की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि यदि पश्चिम बंगाल से कट मनी को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, किसानों को उनका अधिकार देना है और राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना है तो तृणमूल कांग्रेस को घर बैठाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सेवा का अवसर देना होगा। अंत में उन्होंने नारा दिया 'जय मां दुर्गा, जय मां काली, शेष करो एई अत्याचारी'।

'कृषक सुरक्षा' ग्राम सभा में मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकुल रॉय, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा, भाजपा सांसद सुश्री लॉकेट चटर्जी, सांसद श्री स्वप्न दासगुप्ता एवं बर्द्धमान पूर्व के सांसद श्री सुनील मंडल सहित हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित थी। ■

भारत के लोगों को भाजपा नेतृत्व पर पूरा भरोसा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने 3 जनवरी 2021 को गुजरात का दौरा किया और पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कीं। दोनों ने गांधीनगर में एक बैठक में भाग लिया, जिसमें गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी और उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और गुजरात भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया।

श्री नड्डा ने गुजरात प्रदेश भाजपा से आग्रह किया कि वह गुजरात के लोगों के लिए लगातार काम करते रहे और आशा व्यक्त की कि राज्य जल्द ही कोविड-19 महामारी की विषमताओं से बाहर निकालने में कामयाब होगा।

श्री नड्डा ने हाल ही में हुए उप-चुनावों में सभी आठ विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए गुजरात भाजपा को बधाई दी। उन्होंने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इस ही तरह की जीत हासिल करने की कामना की।

श्री नड्डा ने कहा कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं पर गर्व है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब अन्य सभी दल भी तालाबंदी में चले गए थे, तो केवल भाजपा कार्यकर्ता ही देश के लोगों की सेवा करने के लिए आगे आये।

श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने के तरीके की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को भाजपा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि इस महामारी के दौरान भी भाजपा चुनावों में विजयी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने देश का विरोध करना भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात वह राज्य है जिसने भाजपा को राजनीतिक समझ और अनुशासन प्रदान किया है। हमें गुजरात के लोगों के लिए उसी दृष्टि से काम करना होगा, जैसा हमने हमेशा किया है। इस साल हम कोविड-19 महामारी के चलते बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, लेकिन इसका समाधान भी जल्द निकल जायेगा।

बैठक के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी ने कांग्रेस को एक 'डूबता जहाज' बताया, और कहा कि श्री नड्डा की इस यात्रा से भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है और यह एक डूबती हुई नाव है। कांग्रेस में अराजकता घर कर चुकी है।

श्री रूपानी ने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और विपक्षी कांग्रेस का इस तरह सफाया हो जाएगा कि वह दूरबीन से खोज करने पर भी दिखाई नहीं देगी। ■

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी-मदार खंड और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू खुर्जा-न्यू भाऊपुर खंड देश को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के रेवाड़ी-मदार खंड और 29 दिसंबर, 2020 को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के न्यू खुर्जा-न्यू भाऊपुर खंड देश को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी को न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी–मदार खंड

पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे (वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का रेवाड़ी-मदार खंड हरियाणा (महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में लगभग 79 किलोमीटर) और राजस्थान (जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों में लगभग 227 किलोमीटर) में स्थित है। इसमें नौ नवनिर्मित डीएफसी स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से छह– न्यू डबला, न्यू भगेगा, न्यू श्री माधोपुर, न्यू पचार मलिकपुर, न्यू सकून और न्यू किशनगढ़-क्रॉसिंग स्टेशन हैं। जबकि अन्य तीन– रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा– जंक्शन स्टेशन हैं।

इस खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी-मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ इलाके में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ होगा और यह काठुवास में स्थित कॉनकोर के कंटेनर डिपो के बेहतर इस्तेमाल को भी संभव बनायेगा। यह खंड गुजरात में स्थित कांडला, पिपावाव, मुंधरा और दाहेज के पश्चिमी बंदरगाहों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा। इस खंड के उद्घाटन के साथ डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के बीच निर्बाध संपर्क संभव हो जायेगा।

डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का परिचालन

डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन के परिचालन में 25 टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा। इसे डीएफसीसीआईएल के लिए आरडीएसओ के वैगन विभाग द्वारा डिज़ाइन किया गया है। बीएलसीएस–ए और बीएलसीएस–बी वैगनों की प्रतिकृति के परिचालन के परीक्षण पूरे हो चुके हैं। यह डिजाइन क्षमता उपयोग और एक समान वितरित एवं पॉइंट लोडिंग को अधिकतम स्तर पर ले जायेगा। कंटेनर इकाइयों के लिहाज से डब्ल्यूडीएफसी पर एक लॉन्ग हॉल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन में जुड़े ये वैगन भारतीय रेलवे की वर्तमान क्षमता की तुलना में चार गुना अधिक कंटेनर इकाइयों को ढो सकते हैं।

डीएफसीसीआईएल भारतीय रेलवे की पटरियों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा अधिकतम गति के मुकाबले 100 किलोमीटर प्रति

घंटे की अधिकतम गति से मालगाड़ियां चलाएगा, वहीं भारतीय रेलवे की लाइनों पर मालगाड़ियों की 26 किलोमीटर प्रति घंटे की मौजूदा औसत गति को बढ़ाकर डीएफसी पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जाएगा।

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का न्यू भाऊपुर–न्यू खुर्जा खंड

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी) का 351 किलोमीटर लम्बा न्यू भाऊपुर–न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन स्थानीय उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम उद्योग (कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र), डेयरी क्षेत्र (औरैया जिला), कपड़ा उत्पादन/ब्लॉक प्रिंटिंग (इटावा जिला), कांच के सामान के उद्योग (फिरोजाबाद जिला), पॉटरी (बुलंदशहर जिले के खुर्जा), हींग उत्पादन (हाथरस जिला) और ताले और हार्डवेयर (अलीगढ़ जिला) के लिए नए अवसर खोलेगा। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर–दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़-भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनें चलाने में सक्षम करेगा।

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर एक नजर

ईडीएफसी (1856 मार्ग किमी) लुधियाना (पंजाब) के पास साहनेवाल से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा किया जा रहा है, जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में स्थापित किया गया है। डीएफसीसीआईएल पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1504 मार्ग किमी) का निर्माण भी कर रहा है जो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ता है और यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरेगा। ■

दिसंबर-2020 में हुआ 1,15,174 करोड़ रुपये का सर्वाधिक जीएसटी राजस्व संग्रह

दिसंबर-2020 में 1,15,174 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में सीजीएसटी 21,365 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 27,804 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 57,426 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 27,050 करोड़ रुपये की राशि सहित), 8,579 करोड़ रुपये की उपकर राशि (वस्तुओं के आयात पर वसूल की गई 971 करोड़ रुपये की राशि सहित) शामिल है। 31 दिसंबर, 2020 तक नवम्बर माह के लिए कुल 87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल की गई।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी से 23,276 करोड़, एसजीएसटी से 17,681 करोड़ रुपये का निपटान किया। दिसंबर, 2020 में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार है- सीजीएसटी के लिए 44,141 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 45,485 करोड़ रुपये।

जीएसटी राजस्व में वसूली की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप दिसंबर, 2020 में पिछले साल के इसी माह की तुलना में जीएसटी राजस्व 12 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले साल दिसंबर माह की तुलना में इस माह के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 27 प्रतिशत अधिक रहा तथा घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व आठ प्रतिशत ज्यादा रहा।

जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक दिसंबर, 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व सर्वाधिक रहा और पहली बार इसने 1.15 लाख करोड़ के स्तर को पार किया। अब तक सबसे अधिक जीएसटी वसूली अप्रैल, 2019 में 1,13,866 करोड़ रुपये की रही थी। अप्रैल में सामान्य रूप से अधिक राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि वह अप्रैल की रिटर्न से संबंधित होता है और

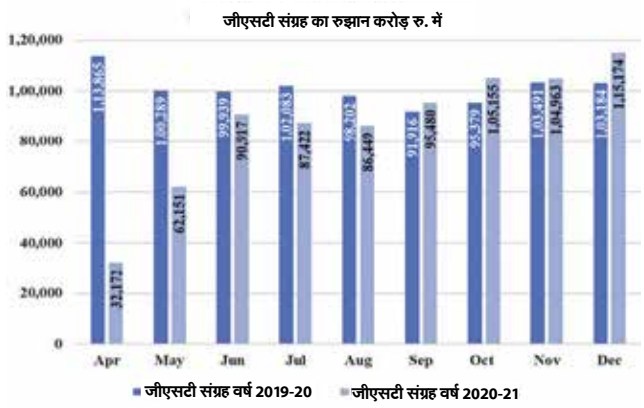

मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम मास होता है।

दिसंबर, 2020 में पिछले मास के 104.963 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले 21 महीनों में मासिक राजस्व में यह सबसे अधिक बढ़ोतेरी है। ऐसा महामारी के बाद त्वरित आर्थिक रिकवरी और जीएसटी की चोरी करने वालों और नकली बिल बनाने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ-साथ अभी हाल में शुरू किए गए व्यवस्थागत परिवर्तनों के कारण संभव हुआ है, जिसके कारण अनुपालन में सुधार को बढ़ावा मिला है।

अभी तक जीएसटी से 1.1 लाख करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है जो जीएसटी की शुरुआत से तीन गुणा अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यह लगातार तीसरा महीना है जब अर्थव्यवस्था में महामारी के बाद रिकवरी के संकेत मिले हैं और जीएसटी राजस्व एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ है। ■

भारत में कोविड-19 से स्वस्थ हुए एक करोड़ से अधिक मरीज

स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों की तुलना में 44 गुना

भारत ने 7 जनवरी को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। कुल मिलाकर अब तक कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक (1,00,16,859) हो गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण मुक्ति दर और भी बढ़कर 96.36 प्रतिशत हो गई है। संक्रमित मरीजों तथा स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या के बीच का अंतर (97,88,776) लगातार बढ़ रहा है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों की तुलना में 44 गुना है।

देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या आज 2,28,083 हैं, जो अब तक के कुल मामलों की तुलना में केवल 2.19 प्रतिशत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण से मुक्त होने की दर 96.36 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का अनुसरण करते हुए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में संक्रमण से मुक्त होने की दर 90 प्रतिशत से अधिक है।

भारत में संक्रमण से मुक्त होने की दर विश्व में सबसे अधिक है। संक्रमण के अधिक मामले वाले देशों में भारत की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने की दर कम है। जांच सुविधाएं बढ़ाने से भारत में संक्रामकता दर भी कम हुई है। दैनिक संक्रामकता दर 3 प्रतिशत से कम है। 17 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में साप्ताहिक संक्रामकता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में नए स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या का 79.08 प्रतिशत हिस्सा पाया गया है। ■

अनाजों, गन्ना, चुकन्दर आदि से इथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने हेतु एक योजना को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर को देश में पहली पीढ़ी (1 जी) के इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनाजों (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और जवार), गन्ना, चुकन्दर आदि से आसवन के जरिए इथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने निम्न बिन्दुओं को मंजूरी दीः

निम्न श्रेणियों को इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की एक संशोधित योजना लाई जाए:

- इथेनॉल उत्पादन के लिए अनाज आधारित भट्टियों की स्थापना करना/मौजूदा अनाज आधारित भट्टियों का विस्तार करना, लेकिन इस योजना के लाभ केवल उन्हीं भट्टियों को मिलेंगे, जो अनाजों की सूखी पिसाई की प्रक्रिया (dry milling process) का इस्तेमाल करेंगी।
- इथेनॉल उत्पादन के लिए गुड़ शीरा आधारित नयी भट्टियों की स्थापना/मौजूदा भट्टियों का विस्तार (चाहे वे चीनी मिलों से संबद्ध हो या उनसे अलग हो) और चाहे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शून्य तरल डिस्चार्ज (जेडएलडी) को हासिल करने के लिए स्वीकृत कोई भी अन्य तरीका कायम करना हो।
- इथेनॉल उत्पादन के लिए अनाज और शीरा दोनों का दोहरा इस्तेमाल करने वाली नयी भट्टियां स्थापित करना और पहले से संचालित भट्टियों का विस्तार करना।
- मौजूदा गुड़ शीरा आधारित भट्टियों (चाहे चीनी मिलों से संबद्ध हो या पृथक हो) को दोहरे इस्तेमाल (गुड़ शीरा और अनाज/कोई भी अन्य खाद्यान्न) में बदलना और अनाज आधारित भट्टियों को भी दोहरे इस्तेमाल वाली भट्टियों में बदलना।
- चुकन्दर, ज्वार और अनाज आदि जैसे अन्य खाद्यान्न से इथेनॉल निकालने के लिए नयी भट्टियां स्थापित करना/मौजूदा भट्टियों का विस्तार करना।

इस प्रस्तावित कदम से विविध प्रकार के अनाजों से पहली पीढ़ी के इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि होगी, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा और इथेनॉल को ऐसे ईंधन के तौर पर प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जो स्वदेश में उत्पादित, गैर-प्रदूषणकारी और अक्षय होगा तथा जिससे पर्यावरण और इको-सिस्टम में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप देश के तेल आयात व्यय की बचत की जा सकेगी। यह किसानों को उनके बकाये का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित करेगा।

2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और रसायन एवं अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,400 करोड़ लीटर एल्कोहल/इथेनॉल की जरूरत होगी। इसमें से 1,000 करोड़ लीटर की जरूरत 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और 400 करोड़ लीटर की जरूरत रसायन एवं अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होगी। 1,400 करोड़ लीटर की कुल जरूरत में से 700 करोड़ लीटर की आपूर्ति चीनी उद्योग और 700 करोड़ लीटर की आपूर्ति अनाज आधारित भट्टियों को करनी होगी।

खाद्यान्न से 700 करोड़ लीटर इथेनॉल/एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए करीब 175 लाख मीट्रिक टन अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा। अतिरिक्त अनाज के इस उपयोग से अंततः किसानों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य और निश्चित खरीदार मिलेंगे। इस तरह देश के करोड़ों किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। ■

27 जिलों, 458 ब्लॉकों, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों में 'हर घर जल' लक्ष्य हासिल

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने 7 जनवरी को सरकार के प्रमुख कार्यक्रम– जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गोवा 100 प्रतिशत पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। अभी तक 27 जिलों, 458 ब्लॉकों, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों को 'हर घर जल' लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है। हाल में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कुरुक्षेत्र देश का 27वां और हरियाणा का तीसरा जिला हो गया है। श्री कटारिया ने बताया कि तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, केंद्रशासित पुद्दुचेरी 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के निकट हैं।

श्री कटारिया ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अगस्त, 2019 तक कुल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों (कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से) नल के पानी के कनेक्शन थे, लेकिन एक वर्ष की कम अवधि में इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 3.04 करोड़ नए कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ने 'कोई व्यक्ति न छूटे' का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पाइप जल कनेक्शन देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ■

अपनी विचारधारा सहयोग पर आधारित

दीनदयाल उपाध्याय

गतांक का शेष...

पाश्चात्य जगत में यह मानकर चलते हैं कि इस प्रकार के संघर्ष, इस प्रकार की लड़ाई, इस प्रकार का वर्ग संघर्ष यह उनके सारे विचार की भूमिका है। यह आज की उनकी भूमिका नहीं है, बिल्कुल प्रारंभ की है। ईसाइयों ने स्वयं अपने मत में यही संघर्ष अपने सामने लाकर रखा। एक ओर उन्होंने शैतान और दूसरी ओर ईश्वर को रखा तथा कहा कि दोनों में यह संघर्ष बराबर चल रहा है। उसमें ही उन्होंने यह निश्चित कर दिया कि जिनके पास धन है, संपत्ति है, उत्पादन के साधन हैं, उनको उन्होंने पूंजीपति कहा, इन पूंजीपति और मेहनत करनेवाले मज़दूरों में स्थायी रूप से संघर्ष चल रहा है। श्रमिकों को ही पूर्णतः प्रमुखता देकर पूंजीपतियों को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। सारी सत्ता श्रमिकों को अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। फिर उसमें राजनीतिक शक्ति यही विचार प्रमुख है। यही एक विचार अपने सामने लेकर चलते चले जा रहे हैं। यह संघर्ष की भूमिका है। एक-दूसरे के बारे में मूलतः विश्वास न करके दूसरों के साथ अपना संबंध यदि आता है, तो वहां संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि दो व्यक्ति मिलते भी हैं तो इसलिए मिलते हैं कि उनके समान स्वार्थ हैं। जहां समान स्वार्थों की भूमिका है, वहां पर दो व्यक्ति मिल सकते हैं। चूंकि सभी पूंजीपति मिल चुके हैं, इसलिए दुनिया के सभी मज़दूर यदि उनका मुक़ाबला करना है तो एक होकर संघर्ष में जुट जाएं। सभी के स्वार्थ एक हैं। समान हितों के लिए मिल जाना चाहिए। यहां एक व्यक्ति का संबंध एक व्यक्ति के बीच केवल स्वार्थ पर ही आधारित है। इसके आगे उसमें कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं। यदि राष्ट्र के संबंध में विचार किया तो वहां भी स्वार्थ की ही भूमिका है। राष्ट्र के संबंध में उनकी कल्पनाएं ये हैं कि एक देश में रहनेवाले लोग जिनके समान स्वार्थ हैं, ऐसे लोगों का मिला एक राष्ट्र है, इसके अतिरिक्त कोई विचार नहीं। वे लोग जब मिलते हैं तो वह भी स्वार्थ के आधार पर, जैसे कुछ लोगों को मिलाकर एक joint stock company बनती है। सभी लोग अपने-अपने पैसे देकर शेयर ख़रीदते हैं। शेयर ख़रीदने के बाद उनकी कुछ Liabilities हैं। लिमिटेड कंपनी बनकर एक फर्म बन जाती है। सबके समान स्वार्थ रहते हैं।

Partnership तैयार हो जाती है। उस Partnership में स्वार्थी लोग लाभ की आशा से एकत्र हो जाते हैं, स्वार्थ का ही विचार करके चलते हैं। उसके आगे का विचार करने के लिए तैयार नहीं। यदि राष्ट्र का विचार करेंगे, मानवता का विचार करेंगे तो उसका भी आधार समान हित, समान स्वार्थ है। सब मानवों को मिलकर समान स्वार्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें युद्ध की विभीषिका के संबंध में एक विद्वान् व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए थे। यदि दस-पांच एटम बम छोड़ दिए गए तो लोगों की संख्या घट जाएगी और जो बच जाएगा, उस पर इतने घातक परिणाम होंगे कि उसको मानव ही कहना कठिन होगा। इस प्रकार कठिन परिस्थिति चली आ रही है। इसलिए अमरीका और रूस को मिल जाना चाहिए। युद्ध बंद कर देना चाहिए। वे आपस में मिलकर क्या करें तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में सभी लोग मंगल तथा अन्य ग्रहों पर पहुंच जाएंगे और मंगल ग्रह के मानव बहुत ही सभ्य और विज्ञान की दृष्टि से बहुत विकास कर चुके हैं। अतः संभवतः हमारे वहां पहुंचने पर उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। यहां के राष्ट्रों में अब आपस में लड़ाई तो पिछले जमाने की बात हो गई है। यह लड़ाई बंद करके अब पृथ्वी पर रहनेवाले मानवों को मंगल ग्रह पर रहनेवाले मानवों से लड़ना चाहिए।

इस प्रकार शांति से भी उनकी संघर्ष की दृष्टि है। यहां के और वहां के प्राणियों में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है, परंतु वे हैं एक ही और आपस में मिलकर शक्ति, बुद्धि सबका सहयोग के साथ विकास करेंगे, इसका विचार नहीं। कुछ प्राणिशास्त्रियों का कहना है कि चींटी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है। उसके पास मनुष्य से कम बुद्धि नहीं। यदि उनका आकार मनुष्य से कुछ छोटा रहे, परंतु बुद्धि के साथ-साथ उसमें कुछ शक्ति भी होती तो वह संभवतया मनुष्य पर विजय प्राप्त करके ही रहती। चींटी के पास केवल अभाव है शक्ति का, मनुष्य के पास उसकी तुलना में अधिक शक्ति हो गई। शक्ति अधिक प्राप्त होने के कारण चींटी चींटी ही रहेगी। यदि कहीं ऐसी कल्पना करें कि चींटी को बिल्ली का शरीर मिल जाए तो वह अधिक सशक्त हो जाएगी। तो हम सब मानव मिलकर उनके ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ेंगे। यह भूमिका संघर्ष की भूमिका है। वे इस भूमि को लेकर खड़े हैं। इसके बाद का विचार आएगा कि छोटे से बड़े तक सभी जगह सब संघर्ष की भूमिका है। हर एक अपने-अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने-अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर चलें।

इसलिए उसमें अधिकार का विचार आता है। पश्चिम में स्वेच्छा से विवाह होने के उपरांत पति और पत्नी के रूप में आने के बाद उनकी कल्पना क्या चलती है? मानो पति पत्नी के अधिकारों को समाप्त करना चाहता है। अतः पत्नी को बराबर सजग रहना चाहिए। इतने होने के बाद

पत्नी पति के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करती है। पति और पत्नी में संघर्ष की भूमिका खड़ी होती है। यदि सड़क पर चलते-चलते व्यक्ति किसी मोटर से टकरा जाए, दुर्घटना हो जाए और यह विचार करके चले कि सदैव मनुष्य मोटर से टकराता ही रहेगा। यदि कोई जेबकतरा सड़क पर किसी की जेब कतर ले और सदैव मन में यही भूमिका बनाकर चले कि हमारे आगे-पीछे, दाएं-बाएं जो चल रहे हैं, सभी जेबकतरे होंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। यदि रेल में कभी कोई डाकू आकर लूट ले, ऐसी घटनाएं होती भी हैं, परंतु कोई यह समझने लगे कि जो भी डिब्बे में घुसा, वह डाकू ही होगा। यह धारणा भ्रामक है। पश्चिम का आधार इसी धारणा पर टिका है। वह यह संघर्ष की भूमिका मानकर चलते हैं कि राजा और प्रजा के बीच में एक संघर्ष की स्थिति है। राजा का संघर्ष करना धंधा ही है, वह प्रजा के अधिकार छीनेगा ही। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच संघर्ष रहेगा।

इसी प्रकार यदि देखें, उस मालिक ने, जिसने अनेक कष्ट सहकर संयम रखकर अपना तथा बाप-दादों का पैसा लगाकर एक कारख़ाना खड़ा किया। उधर मज़दूर काम करने के लिए आते हैं, उन्हें भी जीविकोपार्जन करना है। अपने बाल-बच्चों को छोड़कर आते हैं। दोनों मिलते हैं, काम चलता है। दोनों में संघर्ष की भूमिका है। दोनों एक-दूसरे के अधिकार छीनते हैं। दोनों के अलग-अलग हित हैं तो वही संघर्ष खड़ा होता है। वास्तव में दोनों कारखाने में बैठते हैं, दोनों प्रयत्न करते हैं। चीज़ तैयार होती है। दोनों के सामान्य हित हैं। अगर कहीं दोनों के बीच में विरोध भी खड़ा हो गया तो उस विरोध को सामान्य स्थिति मानकर नहीं चलते। वह विरोध विकृति का द्योतक है। वह विकृति है, वह सामान्य स्थिति नहीं। किंतु पश्चिम का जगत् इस स्थिति को सामान्य मानकर चलता है। यह कहते हैं कि वह विरोध है, तो यह विरोध वाली दृष्टि है। हम इसको विरोध नहीं मानते। हम दूसरे प्रकार से विचार करते हैं। हमारी उसकी एक समान हस्ती है, उस आधार पर एकता है। सत्य और शक्ति मेरे अंदर है, वह उसके अंदर भी है। इस आधार पर हम लोगों के बीच में समानता का नाता है। हमने उनको प्रमुखता दी। अतः किसी स्वार्थ के आधार पर विचार नहीं करते कि हमें समान स्वार्थों को लेकर दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष करना है।

हमारा दृष्टिकोण पश्चिम के दृष्टिकोण से भिन्न है। जैसे पश्चिम अपना-अपना विचार करके चलते हों और वहां एक कहावत भी बन गई है–Every man for himself and devil takes the hind most. प्रत्येक आदमी अपनी-अपनी फ़िक्र करता है और जो सबके पीछे रह जाएगा तो पिछड़ जाएगा। उसकी चिंता कौन करेगा तो शैतान, मतलब यह कि जो पीछे पिछड़ गया, उसकी उपेक्षा होगी। यह सच्चाई जीवन में नहीं चलती। बल्कि देखेंगे कि जीवन इससे उल्टे आधार पर चलता है।

घर में देखते हैं, परिवार है, यदि परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कुछ काम नहीं कर सका, वह किसी के मतलब का नहीं रहा, अतः उसके लिए भोजन क्यों बनाना? जो परिवार में fittest है, उसे पहले और यदि बचा तो बीमार को बाद में देना। ऐसा होता नहीं। जैसे फैक्टरी में अच्छा माल बना, उसे बिकने के लिए बाज़ार में भेज दिया और जो ख़राब हुआ उसे अस्वीकार कर देते हैं। उसी प्रकार यदि बीमार हो गया तो उसे समुद्र में फेंक दो, ऐसा नहीं होता। होता उलटा है, यदि वह बीमार हो गया तो उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। जैसे कि व्यक्ति कमाता है, यदि बाहर से घूमकर आया और मां को बीमार देखकर, सिनेमा जाने का यद्यपि अपने मित्रों से पहले तय करके आया, तो भी उनको लौटा देता है। कहता है कि मेरी मां बीमार है, मुझे उसे दवा देनी है, सेवा करनी है, मैं नहीं जा सकूंगा। पास में यदि पैसा होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा, उसकी फ़ीस देगा, दवा देगा। लेकिन यह नहीं कहेगा कि मां पड़ी रहे, मैं तो सिनेमा जाऊंगा। उसकी मुझे क्या चिंता करनी है? ऐसा विचार नहीं करता।

• अपने यहां संघर्ष नहीं खड़ा होता। जहां प्रेम होगा, वहां संघर्ष न होगा। हमारी प्रेरणा अधिकारों की नहीं है, अपितु कर्तव्य की है। हम कर्तव्य को आधार लेकर चलते हैं। हम सेवा का विचार करते हैं। अपनी एकात्मता है, उसका अनुभव करते हैं। एकात्मता का अनुभव करने के बाद उसके प्रति सहिष्णुता का विचार करते हैं। हम कर्तव्य का भाव लेकर चलते हैं। सहिष्णुता का भाव लेकर चलते हैं। हमारे यहां तो सहिष्णुता है।

मां का छोटा बच्चा है, वह दिन-रात उसका पालन करती है। तो क्या मां और बेटे दोनों की लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है? यदि यह दृष्टि होती तो शायद बेटे का पालन संभव न होता। मां और बेटे के बीच कोई लड़ाई है। यहां पर मां-बाप विवाह करते हैं। परंतु अपने यहां संघर्ष नहीं खड़ा होता। जहां प्रेम होगा, वहां संघर्ष न होगा। हमारी प्रेरणा अधिकारों की नहीं है, अपितु कर्तव्य की है। हम कर्तव्य को आधार लेकर चलते हैं। हम सेवा का विचार करते हैं। अपनी एकात्मता है, उसका अनुभव करते हैं। एकात्मता का अनुभव करने के बाद उसके प्रति सहिष्णुता का विचार करते हैं। हम कर्तव्य का भाव लेकर चलते हैं। सहिष्णुता का भाव लेकर चलते हैं। हमारे यहां तो सहिष्णुता है। उससे आगे बढ़कर विचार करने का है। प्रत्येक के विचार को सुनो, वह जो शब्द कहता है, उसमें भी सच्चाई कितनी है, उसकी सच्चाई को भी सुनना चाहिए। उसको भी समझना चाहिए। इस प्रकार सहिष्णुता का भाव हमारे अंदर आता है, त्याग का भाव आता है। सेवा का भाव जीवन में आता है, एक-दूसरे के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है, सामंजस्य स्थापित होता है। ■

क्रमशः

-संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : हरिगढ़ (5 जून, 1962)

विजया राजे सिंधिया: त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति

(12 अक्टूबर, 1919 – 25 जनवरी, 2001)

राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 सागर, मध्य प्रदेश के राणा परिवार में हुआ था। राजमाता विजया राजे सिंधिया के पिता श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर जालौन ज़िला के डिप्टी कलेक्टर थे और उनकी माता श्रीमती विंदेश्वरी देवी थीं। विजया राजे सिंधिया का विवाह के पूर्व का नाम 'लेखा दिव्येश्वरी' था। विजया राजे सिंधिया के पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, पुत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं।

विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता था। भारत के

विशालतम और संपन्नतम राजे-रजवाड़ों में से ग्वालियर एक था। उस रियासत के महाराजा के साथ उनका विवाह हुआ था। 1957 में विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और वे विजयी हुईं। अपने पति की मृत्यु के बाद सन् 1962 में कांग्रेस के टिकट पर वे संसद सदस्य बनीं। पांच साल के बाद अपने सैद्धांतिक मूल्यों के कारण वे कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में शामिल हो गईं। एक राज परिवार से रहते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गईं। शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आईं।

राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थीं। राजमाता ने जनसंघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं जैसे– श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ काम किया। यही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1967 में मध्य प्रदेश में सरकार गठन में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजया राजे सिंधिया का सार्वजनिक जीवन जितना प्रभावशाली और आकर्षक था, हालांकि व्यक्तिगत जीवन में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

सन 1989 के आम चुनाव में विजया राजे सिंधिया एक बार फिर गुना से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कीं। इससे पहले 22 साल पूर्व सन् 1967 में राजमाता वहां से जीती थीं। 1991 के चुनाव में पुनः विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किया।

राजमाता ने आम आदमी की तरह जीवन जिया

राजमाता सिंधिया सिद्धांतों के प्रति समर्पित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत विदुषी जननायक थीं। उन्होंने महलों के वैभव को छोड़कर जनता के न्याय के लिए संघर्ष का मार्ग स्वीकार किया और सड़कों पर उतरकर राजमाता से लोकमाता बन गईं। राजमाता ने जीवनपर्यन्त आम आदमी की तरह जीवन जिया, सेवा की उनमें ललक थी। सादगी और सरलता उनका स्वभाव था।

राजमाता सिंधिया लंबे समय तक महिलाओं से जुड़ी रहीं और उन्हें सदैव प्रेरित करती थीं। वे हमेशा सेवा के लिए समर्पित रहीं। उन्हें पद और सत्ता ने कभी आकर्षित नहीं किया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया।

राजमाता त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने जनसेवा से कभी अपना मुख नहीं मोड़ा। राजमाता का सपना था कि जब देश में कमल खिलेगा तभी अंतिम सांस लेंगी। ये स्वप्न पूरा हुआ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सन् 1998 से राजमाता का स्वास्थ्य ख़राब रहने लगा और 25 जनवरी, 2001 में राजमाता विजया राजे सिंधिया का निधन हो गया। ■

सरकार का लक्ष्य कृषि लागत घटाना व किसानों को मिले सही मूल्यः नरेन्द्र मोदी

पीएम किसान सम्मान निधि के शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के खातों में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी कर दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक बटन पर क्लिक से देश में 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के खातों में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर दुःख जताया कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के 23 लाख से ज्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन राज्य सरकार ने लंबे समय से सत्यापन प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।

उन्होंने कहा कि जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित में नहीं बोलते हैं, वे यहां दिल्ली आकर किसानों के बारे में बात करती हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों को आजकल एपीएमसी-मंडियों की चिंता सता रही है, लेकिन ये दल बार-बार यह भूल जाते हैं कि केरल में एपीएमसी मंडियां नहीं हैं और इन लोगों ने केरल में कभी आंदोलन नहीं किए।

• इन कृषि सुधारों से किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इन कानूनों के बाद किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की लागत घटाने के लक्ष्य पर काम किया है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, सौर पम्पों के वितरण की योजना जैसी सरकार की कुछ किसान केन्द्रित पहल गिनाईं, जिनसे किसानों की लागत घटाने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसानों को एक बेहतर फसल बीमा सुरक्षा मिले। आज, करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय से अटकी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के तहत किसानों के लिए उत्पादन लागत की तुलना में डेढ़ गुना एमएसपी तय किया। उन्होंने कहा कि उन फसलों की संख्या भी बढ़ गई है, जिनके लिए एमएसपी उपलब्ध है।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार का फसलों की बिक्री को किसानों के लिए नए बाजार खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने छोटे किसानों के समूह बनाने की दिशा में काम किया है, जिससे वे अपने क्षेत्र में एक सामूहिक बल के रूप में काम कर सकते हैं। आज, देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्थापना का काम जारी है, जिन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों को पक्के मकान, शौचालय और पाइप से स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन से काफी फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार से किसानों के जीवन की बड़ी चिंता कम हो गई है।

श्री मोदी ने कहा कि इन कृषि सुधारों से किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। इन कानूनों के बाद किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं। वे जहां भी अच्छा मूल्य मिले, वहां पर अपनी उपज बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के बाद किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं या निर्यात कर सकते हैं या किसी व्यापारी को बेच सकते हैं, या किसी अन्य राज्य में बेच सकते हैं, या एफपीओ के माध्यम से बेच सकते हैं या बिस्कुट, चिप्स, जैम, अन्य उपभोक्ता उत्पादों की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकते हैं। ■

किसानों को 18,089 करोड़ रु. की राशि सीधे उनके खातों में भेजा जाना सुशासन की दृष्टि से बड़ा कदमः जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती एवं सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर देश के 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 18,000 करोड़ रु. की धनराशि हस्तांतरित करने के लिए उनका हृदय से धन्यवाद।

उन्होंने कहा कि 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,089 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में भेजा जाना, सुशासन की दृष्टि से बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में 8 करोड़ लोगों ने अपने को पंजीकृत कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन को सुना, जो कि अभूतपूर्व है।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने कई दशक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद आपके लिए कुछ नहीं किया, उनके फैलाए झूठ में ना आएं, उनसे सावधान रहें। हमारे किसान भाइयों व देश को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें।

उन्होंने कहा कि ये दुख की ही बात है कि जहां देशभर के करोड़ों किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान इसके लाभ से वंचित हैं। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसान हितैषी इस योजना को, बंगाल में लागू क्यों नहीं किया?

"मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने कई दशक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद आपके लिए कुछ नहीं किया, उनके फैलाए झूठ में ना आएं, उनसे सावधान रहें। हमारे किसान भाइयों व देश को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें,,

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की संगठनात्मक नियुक्तियां

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 31 दिसंबर, 2020 को नए संगठनात्मक दायित्वों की घोषणा की। राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) श्री वी. सतीश को संगठक एवं राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) श्री सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, वहीं राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) श्री शिव प्रकाश दायित्वों में कुछ परिवर्तन के साथ इसी पद पर बने रहेंगे।

श्री वी. सतीश
संगठक

श्री सौदान सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री शिव प्रकाश
राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री

नाम	दायित्व	केंद्र	विशेष ध्यान
श्री वी. सतीश	संगठक	दिल्ली	संसदीय कार्यालय समन्वय, एस.सी., एस.टी. मोर्चा समन्वय, विशेष संपर्क
श्री सौदान सिंह	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	चंडीगढ़	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़
श्री शिव प्रकाश	राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री	भोपाल	मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल

जयराम ठाकुर सरकार ने तीन वर्षों में विकास की नई गाथा लिखी: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार के तीन वर्षों के सफल कार्यकाल के अवसर पर संदेश जारी करते हुए कहा कि हम सबके लिए यह अत्यंत ही हर्ष एवं गौरव का विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 27 दिसम्बर, 2020 को अपने कार्यकाल के सफल तीन वर्ष पूर्ण कर रही है।

श्री नड्डा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने तीन वर्षों में विकास की नई गाथा लिखी है। प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन, स्वास्थ्य एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कई योजनाओं को शुरू किया है और भाजपा की जयराम सरकार ने इसे जमीन पर उतारने का सार्थक प्रयास किया है। मैं हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी अभिनंदन करता हूं। उनका सदैव ही हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रेम रहा है। उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए प्राकृतिक आपदाओं से जूझने में सहयोग हेतु अगस्त 2018 में एनडीआरएफ की एक विशेष बटालियन की कांगड़ा जिले के नूरपुर में तैनाती की थी। अभी हाल ही में उन्होंने मनाली-लेह मार्ग के दारचा में भागा नदी पर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में चंद्रा नदी पर और मनाली के पलचान में ब्यास नदी पर भव्य पुलों का उद्घाटन किया था जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अटल टनल के भी समय पर पूरे होने में उनकी प्रभावी भूमिका रही। मैं सारे हिमाचल प्रदेश की ओर से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे आज इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।

• प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन, स्वास्थ्य एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कई योजनाओं को शुरू किया है और भाजपा की जयराम सरकार ने इसे जमीन पर उतारने का सार्थक प्रयास किया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुशासन, विकास और जनता की खुशहाली के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आज अपने तीन सफल वर्ष पूरे किये हैं। अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने हिमाचल का समुचित विकास कर नये आयाम स्थापित किए हैं जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। विगत तीन वर्षों में सरकार व जनता के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उठाये गये कारगर कदमों व जयराम ठाकुर सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे हिमकेयर योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, हिमाचल गृहणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना इत्यादि की दिशा में किये गये कार्यों का संकलन एक कॉफी टेबल बुक में दर्शाया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति पिछले तीन दशकों से विशेष स्नेह एवं लगाव रहा है तथा प्रदेश को उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा है, फलस्वरूप प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने एक ओर राज्य को केंद्र से मिलने वाली वितीय अनुदान में वृद्धि की है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने देवभूमि हिमाचल में औद्योगिक विकास के लिए भी कई योजनायें शुरू की हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले करीब नौ माह से पूरा देश एवं प्रदेश कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सेवा ही संगठन' के आह्वान पर अपने आप को जन-सेवा में झोंकते हुए देश भर में मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी संगठन ने सरकार के साथ मिल कर काम करते हुए जरूरतमंदों तक फ़ूड पैकेट्स, राशन किट्स, फेस कवर, सैनिटाइजर इत्यादि का वितरण किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुजुर्गों के लिए दवाई

और भोजन की व्यवस्था की। साथ ही, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के रह रहे लोगों के लिए भी खाने-पीने और दवाई की व्यवस्था की। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के इस अतुलनीय सेवा भाव को शत-शत नमन करता हूं। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर आम जनता की भलाई और उनकी सेवा के लिए समर्पित है। हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे हिमाचल वासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य भी किया है, पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें अपना काफी योगदान दिया है। कोविड महामारी में बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को भी हिमाचल मॉडल अपनाने के लिए कहा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार ''सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'' को अपनाते हुए जन-कल्याणकारी कार्यों को जारी रखेगी और प्रदेश को विकास के नये शिखर की ओर ले जाएगी। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले पंचायत चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास इसी तरह हम बना रहेगा

और उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं प्रदेश सरकार को तीन वर्ष का सफलतम कार्यकाल पूर्ण करने के लिए, कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी पूरी टीम एवं हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ■

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को सराहा

हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर 27 दिसंबर 2020 को वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली से केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दिल्ली में श्री अनुराग ठाकुर ने श्री राजनाथ सिंह का हिमाचल की परंपरा के मुताबिक टोपी व शाल पहनाकर सम्मान किया। इससे पहले भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप के साथ सुबह रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने रिज पर लगी प्रदर्शनी को भी देखा।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल के लिए एक बड़ा तोहफा बताया और कहा कि यह योजना 2002 से अब तक जारी है। चाहे प्रदेश और केंद्र में कितनी सरकारें आईं और गईं, पर यह योजना जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में समर्पित अटल टनल रोहतांग न केवल लाहौल-स्पीति ज़िला के लोगों को लाभान्वित करेगी बल्कि यह सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

हिमाचल सरकार के तीन साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बधाई दी। श्री धूमल ने कहा

कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहला काम बुजुर्गों की पेंशन को लेकर 80 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष किया। इसका लाभ बड़ी संख्या में हुआ।

भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना ने कहा कि केंद्र की योजनाओं और प्रदेश सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं का दायित्व है। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। प्रदेश भाजपा सह-प्रभारी श्री संजय टंडन ने प्रदेश सरकार के तीन साल पूरे होने पर कहा कि मोदी और जयराम सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए जारी होने वाले पैसे को शत-प्रतिशत लोगों की जेब तक पहुंचाया गया है। ■

असम की संस्कृति देश का गहना है: अमित शाह

जो असम हथियारों और अशांति के लिए जाना जाता था वह आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 26 दिसंबर को असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। करीब 850 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। श्री शाह ने असम के अलग-अलग हिस्सों में बनने वाले नौ विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। साथ ही, उन्होंने अहुम दर्शन योजना के अंतर्गत 8000 नामघरों को (असम की पारंपरिक वैष्णवी मठ के तहत) वित्तीय अनुदान भी वितरित किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि जो असम हथियारों और अशांति के लिए जाना जाता था वह आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। पूर्वी भारत में कभी अलग-अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा हुआ करती थी। अलग-अलग समूह हाथ में हथियार लिये दिखते थे, आज वो सारे मुख्यधारा के साथ जुड़े दिखते हैं और वो सारे युवा जो आंदोलन करते थे वो असम के विकास के साथ जुड़कर असम को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश एग्रीमेंट, ब्रू-रियांग समझौता समेत कई प्रयास किए गए। अनेक सालों से चल रहे बोडो आंदोलन को एक समझौता कर असम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम भी श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। श्री शाह ने कहा कि मैं सभी बोडो संगठनों और लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर समझौता किया।

उन्होंने कहा कि हाल के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव में एनडीए की शानदार जीत इसी विश्वास का प्रतीक है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम में चुनाव आने वाले हैं, फिर से ये अलगाववाद की भाषा बोलने वाले चेहरा, रंग-रूप बदलकर लोगों के बीच में आएंगे, लोगों को उल्टा सीधा समझाएंगे। मैं उनसे आज पूछने आया हूं आपने आंदोलन करके असम को क्या दिया? आपने केवल और केवल असम के युवाओं को शहीद करने का काम किया।

• अनेक सालों से चल रहे बोडो आंदोलन को एक समझौता कर असम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम भी श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है।

श्री शाह ने कहा कि असम की संस्कृति देश का गहना है। असम संस्कृति, भाषा और संगीत के लिए लगाव रखने वाला प्रदेश है। भूपेन हजारिका जी न केवल असम बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व के साहित्य और कला के प्रतीक बनकर देश में रहे। मगर भूपेन जी को कोई सम्मान नहीं मिलता था। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भूपेन जी को भारत रत्न देकर हमारे साहित्य और कला को आगे बढ़ाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा राज्यों की पहचान, संस्कृति, भाषा व कला को बल देने में विश्वास करती है। क्योंकि हम मानते हैं जब तक हमारे राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती भारत कभी भी महान नहीं हो सकता। असमिया साहित्य और कला के बग़ैर भारत का साहित्य और कला अधूरे हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास को सदैव प्राथमिकता दी। सालों से असम सरकार के गैस रॉयलिटी का 8000 करोड़ रुपया बाकी था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह स्वयं यहां से 18 साल सांसद रहे मगर रॉयलिटी का मसला हल नहीं कर सके। मोदी जी ने असम की सरकार बनने से पहले ही रॉयलिटी का मसला हल करके असम के विकास के लिए ढेर सारा काम किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने स्वयं 6 साल के अंदर तीस बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए। चाहे अरुणाचल हो चाहे असम, विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गो से जोड़ना, सड़क मार्गो से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को अवसर देना सभी कार्यों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।

श्री शाह ने कहा कि गेंडा जो असम का गौरव है उसका रक्षण करने के लिए मैं असम सरकार को बधाई देता हूं। गेंडों का शिकार करने वाली टोलियां पिछली सरकार के ज़माने में राजकीय आश्रय के साथ असम के गौरव को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोरता से काम करके असम सरकार ने काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। ■

मणिपुर

'पूरे नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं मोदी जी'

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 27 दिसंबर को मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री शाह ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई-ऑफ़िस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना (Thoubal Dam) का उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में आईटी-एसईजेड, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई मणिपुर की विकास यात्रा का आज महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज एक ही दिन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य शुरू होने जा रहे हैं जिनमें चूड़ाचांदपुर में मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, मंत्रिपुखरी में आईटी-एसईजेड सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा-दर्शक बनने का काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि इंफाल में राज्य पुलिस मुख्यालय और स्मार्ट सिटी एकीकृत केंद्र से स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि ट्रिपल आईटी और आईटी-एसईजेड मणिपुर के युवाओं को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेंगे। आईटी-एसईजेड बनने के बाद मणिपुर की जीडीपी में 4600 करोड़ रुपये सालाना की बढ़ोतरी होगी और 44,000 लोगों के लिए रोजगार सर्जन भी होगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से मणिपुर के युवा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने मणिपुर को बंद और ब्लाकेड से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर चलाने का काम किया है। मोदी जी पूरे नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और यहां के लोगों का भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह ने विगत 3 वर्षों में उल्लेखनीय काम किए हैं। पिछले 3 सालों में एक भी बार बंद नहीं हुआ है जिससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों का विकास होता है। श्री बीरेन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मणिपुर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और मणिपुर को नई पहचान देने का काम किया है।

• आईटी-एसईजेड बनने के बाद मणिपुर की जीडीपी में 4600 करोड़ रुपये सालाना की बढ़ोतरी होगी और 44,000 लोगों के लिए रोजगार सर्जन भी होगा

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर-पूर्व में विकास की बाढ़ आ गई है। नॉर्थ-ईस्ट पहले अलगाववाद और अलग-अलग हिंसक आंदोलनों के लिए जाना जाता था, लेकिन विगत साढे 6 वर्षों में एक के बाद एक कई संगठनों ने अपने हथियार डाले हैं और जो बचे-खुचे हैं वह भी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट को इतनी प्राथमिकता पहले कभी नहीं मिली और विशेष बात है कि मोदी जी स्वयं विगत साढ़े 6 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ-ईस्ट आए हैं और सभी राज्यों में दौरे किए हैं जिससे यह साबित होता है कि मोदी जी की नजरों में उत्तर-पूर्व की कितनी प्राथमिकता है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी जी जनता के दिल की बात जानते हैं, यहां के मूल निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट की मांग विगत कई वर्षों से चल रही थी और 11 दिसंबर, 2019 को मोदी जी ने तय किया इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय होगा। देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट प्रदान किया, जो मणिपुर की राज्य की स्थापना के बाद केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ■

'अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मील का पत्थर'

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम की संयुक्त प्रेस वार्ता

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने 29 दिसंबर 2020 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मील का पत्थर बताते हुए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया।

श्री गहलोत ने बताया कि एससी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है। पहले कमिटेड लायबिलिटी के फ़ॉर्मूले के कारण लगभग आधे राज्यों को तो केंद्र से छात्रवृत्ति की राशि ही नहीं मिल पाती थी। कुछ राज्यों को आंशिक छात्रवृत्ति राशि मिलती थी तो कुछ राज्यों को ज्यादा मिलता था। इस योजना में केंद्र का हिस्सा सालाना 1200-1300 करोड़ रुपये ही होता था और अंतिम अंतिम दो वर्षों में तो औसतन 1100 करोड़ रुपये ही था। इतनी कम राशि के कारण दसवीं पास करने के बाद छात्रवृत्ति के अभाव में छात्रों को स्कूल छोड़ने को मजबूर होना पड़ता था। कम बजट के कारण राज्य सरकार भी छात्रवृत्ति देने में कठिनाई महसूस किया करती थी। समय पर छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि भी नहीं मिल पाती थी। इससे एससी वर्ग के छात्रों का ड्रॉप-आउट रेशियो बहुत अधिक हो जाता था। पहले कई ऐसी शिकायतें भी आईं कि राज्य सरकारों ने छात्रवृत्ति योजना का पैसा किसी और मद में लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में राज्यों से विचार करने के लिए लगातार सुझाव आते रहते थे। इन सभी बातों पर चर्चा कर हमने अनुसूचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया।

- **एससी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है।**

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में अनुसूचित वर्ग के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 59,048 करोड़ रुपये की राशि को अनुमोदित किया है जो पहले की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। इसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी जो कुल योजना का 60% है और शेष 40% राशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। इससे नियत समय पर भुगतान हो सकेगा और उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिल पायेगा। उम्मीद है कि दसवीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी न रख पाने वाले लगभग 1.36 करोड़ गरीब छात्रों को अगले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली के दायरे में लाया जा सकेगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकारें ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति स्थिति, आधार पहचान व बैंक खातों के विवरण की जांच कर छात्रों की सूची केंद्र सरकार को सौंपेगी। उच्च शिक्षा में सबसे गरीब परिवारों के छात्रों के नामांकन के लिए अभियान चलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे गरीब छात्रों तक पहुंच को प्राथमिकता दिए जाने की योजना है। इससे पांच वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 4 करोड़ छात्रों को लाभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में एक और प्रावधान किया जा रहा है कि इस योजना के तहत छात्रों के एकाउंट में पहले राज्य सरकार छात्रवृत्ति का पैसा हस्तांतरित करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि हस्तांतरित करेगी। सभी राज्य सरकारें इस योजना से सहमत हैं और उन्होंने इसे लागू करने की संस्तुति दे दी है। डीबीटी के कारण इस योजना में कोई लीकेज नहीं होगा और अनियमितताएं भी खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि में हर वर्ष 5% की वृद्धि करते हुए इसे 80% तक ले जायेगी जिससे राज्य सरकारों पर बोझ काफी कम पड़ेगा। यह योजना इसी वर्ष से लागू हो जायेगी।

केंद्र सरकार मार्च तक लगभग 5,500 करोड़ रुपये का एमाउंट राज्य सरकार को दे देगी।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकारें लगातार अनुसूचित वर्ग के साथ नाइंसाफी करती आई हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकारों ने अनुसूचित जाति के साथ केवल और केवल छल किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने कैसा दुर्व्यवहार किया था, ये हम सब जानते हैं। कांग्रेस की सरकार ने उन्हें 'भारत रत्न' भी नहीं दिया। बाबा साहब धारा 370 नहीं चाहते थे, पाकिस्तान के साथ आर-पार का बंटवारा चाहते थे, महिलाओं को बराबरी का हक देना चाहते थे और वे समान आचार संहिता के भी पक्ष में थे लेकिन पंडित नेहरू उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनका विरोध करते थे। कांग्रेस ने बाबा साहब का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया। दिल्ली में बाबासाहब की न तो समाधि है और न ही संग्रहालय। यह भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जिसने न केवल बाबासाहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि का निर्माण कराया है, बल्कि करोड़ों रुपये की लागत से बाबा साहब का संग्रहालय का निर्माण कार्य भी करा रही है।

श्री गौतम ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद नकली छात्रवृत्ति वाले लगभग 50 लाख लीकेज पकड़े गए। कांग्रेस की सरकारों का यह बहुत बड़ा घोटाला था जो छात्रवृत्ति का पैसा भी हड़प जाया करते थे। पंजाब में 2019 में हमने छात्रवृत्ति के लिए 303.92 करोड़ रुपये दी थी लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को इसमें से 248 करोड़ रुपये निकाले जिसमें से 39 करोड़ रुपये का दस्तावेज अब भी नहीं मिल रहा है।

श्री गौतम ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पांच गुना वृद्धि करते हुए 59,048 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और डायरेक्ट लाभार्थी छात्रों के एकाउंट में सीधे छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। मैं इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। इस प्रेस वार्ता में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य भी उपस्थित थे। ■

यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए सुरक्षा कवच है

लाल सिंह आर्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा

देश में 1944 से अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चालू थी। आजादी के बाद से अभी तक आवश्यक रुपए की व्यवस्था नहीं थी। इस छात्रवृत्ति में कुछ अनियमितताएं भी थीं। कम राशि होने के कारण छात्रों को यदि कुछ नए इंस्ट्रूमेंट लेना है, कुछ टेक्नॉलोजी से जुड़ना है तो नहीं जुड़ पाते थे। राज्य सरकार समय पर पैसा नहीं भेजती थी इन छात्रों को, तो उनको जो भी साधन पढ़ने के लिए खरीदने थे तो वो उससे वंचित रहते थे। इस कारण से बच्चे कहीं न कहीं विद्यालय छोड़ते थे। ऐसी संख्या करोड़ों में है।

पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत एवं उनकी टीम ने एक अध्ययन किया कि आखिर अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक बच्चे जो विद्यालय छोड़ रहे हैं, वो विद्यालय कैसे आएं, उनको पढ़ाई के साधन कैसे मिले, पारदर्शी व्यवस्था कैसे हो, इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि आनेवाले पांच वर्षों की योजना बनाई जाए और उन योजनाओं के तहत इस राशि को कई गुना बढ़ाकर 59 हजार करोड़ रुपए पांच साल में केंद्र सरकार खर्च करेगी। छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा, राज्य में उनके बैंक में खाते खुलेंगे और एक क्लिक से उन छात्रों के खाते में केंद्र सरकार पैसे डालेगी, तो एक पारदर्शी व्यवस्था हो गई।

इस छात्रवृत्ति में छात्रों को लैपटॉप लेना है, रहने की, खाने की ये सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं हैं। एक बड़ी चीज इसमें और की गई है कि पहले 60 लाख बच्चे ही लाभान्वित हो रहे थे, अब इससे प्रतिवर्ष चार करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। एक करोड़ 36 लाख ऐसे बच्चे जो विद्यालय छोड़ गए हैं, उनके लिए सरकार घर-घर चलने का अभियान चलाएगी। उन बच्चों के परिवार और उनके बीच में जाना और उनसे आग्रह करना कि चलिए, आप दोबारा नामांकन करा लीजिए। तो सरकार का ऐसा अनुमान है कि कुल 36 लाख बच्चे पांच साल में पुनः विद्यालय में लौटेंगे। यह कहा जा सकता है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को अगर ईमानदारी से कोई पूरा कर रहा है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है।

कांग्रेस 57 वर्ष हिंदुस्तान में सत्ता में रही, उसके कई प्रधानमंत्री रहे, राज्यों में अनेक वर्षों तक उसके कई मुख्यमंत्री रहे, जो नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा है, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा? अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए सोच लिया होता तो ड्रॉपआउट होता ही नहीं, बच्चे विद्यालय छोड़ते ही नहीं, नए बच्चे और आते। नरेन्द्र मोदी जी का जो ये निर्णय है, वह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पारदर्शी है और अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए सुरक्षा कवच है। ■

(कमल संदेश से बातचीत पर आधारित)

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा की शुरुआत

वर्ष 1955 से लेकर 2014 तक लगभग 13 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, जबकि आज यह 30 करोड़ गैस कनेक्शन तक पहुंचने वाला है

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भुवनेश्वर में 1 जनवरी, 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की, जो कि लोगों का जीवन-यापन आसान बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडियन ऑयल के एलपीजी ग्राहक अब रिफिल बुकिंग के लिए सिंगल मिस्ड कॉल नंबर 8454955555 का उपयोग कर सकते हैं– पूरे भारत के लिए और भुवनेश्वर शहर में नए कनेक्शन के लिए।

इस मौक़े पर श्री प्रधान ने इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित एक्सपी 100 के रूप में ब्रांडेड विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल (ऑक्टेन 100) का दूसरा चरण भी शुरू किया। इस दूसरे चरण में इंडियन ऑयल के ब्रांडेड एक्सपी100 को आज चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, इंदौर और भुवनेश्वर सहित सात और शहरों में शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने एक्सपी100 को पहले चरण में एक महीने पहले 01 दिसंबर, 2020 को 10 भारतीय शहरों के चुनिंदा आउटलेट्स में लॉन्च किया था।

श्री प्रधान ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मिस्ड कॉल सुविधा लोगों को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने और नागरिकों के जीवन-यापन में सुगमता लाने के लिए प्रत्येक भारतीय के साथ समान व्यवहार करने की इच्छुक होने के चलते प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है।

उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर से शुरू की जा रही इस सेवा का विस्तार जल्द ही पूरे देश में किया जाएगा। श्री प्रधान ने गैस एजेंसियों तथा वितरकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की अवधि 1 दिन से कुछ घंटों तक कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश ने एलपीजी वितरण में एक लंबा सफर तय किया है। वर्ष 1955 से लेकर 2014 तक लगभग 13 करोड़ लोगों को

एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन आज यह आंकड़ा 30 करोड़ गैस कनेक्शन तक पहुंचने वाला है, जो एक बड़ी सफलता प्राप्त होने और जनता को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एलपीजी कनेक्शन ने भारतीय महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाया है।

श्री प्रधान ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने में प्रौद्योगिकी की शक्ति के महत्त्व के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने ओडिशा खनन निगम-ओएमसी के वितरण के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से डिलिवरी बॉयज़ को 'कोरोना योद्धा' के रूप में संबोधित किया, जिन्होंने कोविड महामारी के समय में भी बिना किसी रुकावट के लोगों के दरवाजे तक रसोई गैस की आपूर्ति करने की हिम्मत और ईमानदारी दिखाई।

उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया अपने संसाधनों एवं समृद्धि के बावजूद कोरोना के कारण परेशान थी, तब भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिससे पूरा देश संगठित हुआ और भारत की सफलता ने दुनिया के समक्ष एक नया मॉडल प्रस्तुत किया।

असम के डिगबोई में कार्यरत देश की सबसे पुरानी रिफाइनरी से एक्सपी100 की पहली खेप को रवाना करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के पूर्वोदय के विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ■

आईवीआरएस सुविधा पर मिस्ड कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा के फायदे इस प्रकार हैं:

- त्वरित बुकिंग, ग्राहक को लंबे समय तक कॉल होल्ड नहीं करना है।
- आईवीआरएस कॉल में जहां सामान्य कॉल दरें लागू होती हैं, वहीं उसकी तुलना में इस सुविधा में ग्राहकों को कोई कॉल शुल्क नहीं लगता है।
- जो लोग आईवीआरएस सुविधा से परिचित नहीं हैं या वृद्धावस्था वाले ऐसे ग्राहक जो आईवीआरएस का उपयोग करने में समस्याओं का सामना करते हैं, वे सभी मिस्ड कॉल के ज़रिये रिफिल बुकिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं का जीवन और भी आसान होगा।

जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत की शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई-सेहत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री, श्री अमित शाह, डॉ. हर्षवर्धन, डॉ. जितेन्द्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की।

उन्होंने उस विशेष संबंध को भी याद किया जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जम्मू-कश्मीर के साथ था और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का 'इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत' का कथन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा।

जम्मू-कश्मीर आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई-सेहत योजना के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने से जीवन-यापन में सुधार होगा। अभी राज्य के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सेहत योजना के बाद सभी 21 लाख परिवारों को उसी तरह का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना का एक और लाभ यह होगा कि उपचार केवल जम्मू और कश्मीर के सरकारी और निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं है। बल्कि, इस योजना के तहत सूचीबद्ध देश के हजारों अस्पतालों से उपचार का लाभ लिया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने सभी निवासियों के लिए आयुष्मान योजना के विस्तार को ऐतिहासिक बताया और जम्मू-कश्मीर द्वारा अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाने पर खुशी जाहिर की। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का विकास उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि चाहे वह महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसरों, दलितों के उत्थान, शोषित और वंचितों के बारे में हो या लोगों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का सवाल हो, हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए फैसले ले रही है। ■

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए संकल्पित है मोदी सरकार: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ अवसर पर जम्मू-कश्मीर की जनता को हार्दिक बधाई दी और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद किया।

श्री नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित जम्मू-कश्मीर के विकास और जन-जन के कल्याण के लिए संकल्पित आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई सेहत योजना का शुभारंभ कर एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत की है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जिस जम्मू-कश्मीर में विकास सदैव उपेक्षित रहा, वह आज आर्टिकल 370 और 35A के हटने के कारण विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा से जोड़ने का काम तेजी से कर रही है।

श्री नड्डा ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने जिस जिला विकास परिषद् (डीडीसी) चुनाव में भाग लेकर उसे सफल बनाया, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में जो विश्वास दिखाया है, उसे डीडीसी चुनाव में विजयी हुए लोग कायम रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं, जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा तथा प्रदेश की जनता को इस गौरवशाली क्षण पर अत्यंत हर्ष के साथ बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम जम्मू-कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। ■

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को दी मंजूरी

यह योजना न केवल निवेश को प्रोत्साहन देगी, बल्कि 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की दर से जम्मू और कश्मीर में वर्तमान उद्योगों को कार्यशील पूंजी समर्थन प्रदान करके उन्हें विकसित भी करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6 जनवरी को जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रस्ताव पर विचार किया और इसकी स्वीकृति दी। योजना 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2037 तक स्वीकृत की गई है।

भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना के रूप में जम्मू-कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना (जेएंडकेआईडीएस, 2021) तैयार की है। योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रूप में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक विकास पर विचार करते हुए वर्तमान योजना इस विजन के साथ लागू की जा रही है कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और नए निवेश आकर्षित करके तथा वर्तमान उद्योगों को विकसित करके जम्मू और कश्मीर के उद्योग और सेवा क्षेत्र का विकास हो सके।

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे:

- **पूंजी निवेश प्रोत्साहन:** संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) निवेश या भवन निर्माण अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश पर जोन-ए में 30 प्रतिशत तथा जोन-बी में 50 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध है। 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली इकाइयां इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने की पात्र होंगी। जोन-ए तथा जोन-बी में प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा क्रमशः 5 करोड़ रुपये तथा 7.5 करोड़ रुपये है।
- **पूंजी ब्याज सहायता:** संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) निवेश के लिए 500 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षित दर से पूंजी ब्याज सहायता।
- **जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन:** 10 वर्ष के लिए संयंत्र और मशीनरी (मैन्युफैक्चरिंग में) या भवन निर्माण तथा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र में) में वास्तविक निवेश के 300 प्रतिशत पात्र मूल्य तक प्रोत्साहन एक वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि प्रोत्साहन की कुल पात्र राशि से एक दहाई से अधिक नहीं होगी।
- **कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता:** सभी वर्तमान इकाइयों को अधिकतम 5 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनायी गई है। संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये तक निवेश करने वाली छोटी इकाइयों को 7.5 करोड़ रुपये तक पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए पूंजी ब्याज सहायता 6 प्रतिशत की दर से मिलेगी।
- योजना का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास को ले जाना है। यह भारत सरकार की पहली बार शुरू की गई कोई औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश में स्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रयास है।
- जीएसटी से जुड़े प्रोत्साहन को शामिल करके योजना को व्यापार-सुगमता के अनुरूप सहज बनाया गया है। जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन पारदर्शिता से समझौता किये बिना अनुपालन बोझ को कम करना सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख प्रभाव तथा रोजगार सृजन क्षमता

- योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन, कौशल विकास, नए निवेश को आकर्षित करके तथा वर्तमान निवेशों को विकसित करके स्थायी विकास पर बल के साथ जम्मू और कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम में मौलिक परिवर्तन करना है, जिससे जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के औद्योगिक रूप से विकसित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सके।
- आशा है कि प्रस्तावित योजना से अप्रत्याशित निवेश आकर्षित होगा तथा लगभग 4.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ब्याज सहायता के कारण योजना लगभग 35,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देगी।

शामिल व्यय

प्रस्तावित योजना का वित्तीय परिव्यय योजना अवधि 2020-21 से 2036-37 के लिए 28,400 करोड़ रुपये है। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के अंतर्गत 1,123.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ■

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल, जहां मेट्रो रेल बिना ड्राइवर के चलती है: नरेन्द्र मोदी

2014 में केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, लेकिन यह आज 18 शहरों में उपलब्ध है। 2014 में देश में केवल 248 किमी मेट्रो लाइनें परिचालित थीं, लेकिन आज 700 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइनें परिचालित हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन किया। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में शुरुआत की गई। यह कार्ड पिछले साल अहमदाबाद में शुरू किया गया था।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह आयोजन शहरी विकास को भविष्य के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना शासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि कुछ दशक पहले जब शहरीकरण की मांग अनुभव की गई थी, तो भविष्य की जरूरतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि आधे-अधूरे काम किए गए, जिनसे भ्रम की स्थिति बनी रही।

श्री मोदी ने कहा कि इसके विपरीत आधुनिक सोच यह कहती है कि शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के अवसर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इसका हम जीवन की सुगमता को बढ़ाने में भी उपयोग कर सकते हैं।

• शहरीकरण को एक चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के अवसर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि सोच का यह अंतर अब शहरीकरण के हर आयाम में दिखाई दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, लेकिन यह आज 18 शहरों में उपलब्ध है। वर्ष 2025 तक हम इसका 25 से अधिक शहरों में विस्तार करने जा रहे हैं। 2014 में देश में केवल 248 किमी मेट्रो लाइनें परिचालित थीं, लेकिन आज 700 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइनें परिचालित हैं, इस प्रकार इसमें तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2025 तक हम इसका 1700 किमी तक विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि ये केवल आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन को सहज बनाने का प्रमाण भी हैं। यह केवल ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बना बुनियादी ढांचा मात्रा ही नहीं है, बल्कि देश के मध्यम वर्ग, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रमाण भी हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पहली बार मेट्रो नीति तैयार की है और उसे समग्र रणनीति के साथ लागू किया है। स्थानीय मांग के अनुसार काम करने, स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने, मेक इन इंडिया का विस्तार करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर ध्यान दिया गया है कि मेट्रो और यातायात के आधुनिक साधनों का विस्तार शहर के लोगों की जरूरतों और व्यावसायिक जीवन शैली के अनुसार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि विभिन्न शहरों में विभिन्न प्रकार की मेट्रो रेल पर काम किया जा रहा है।

श्री मोदी ने विभिन्न प्रकार की मेट्रो रेल को सूचीबद्ध किया, जिन पर काम किया जा रहा है। दिल्ली और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी एक घंटे से भी कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन शहरों में यात्रियों की संख्या कम है, वहां मेट्रोलाइट रेल पर काम किया जा रहा है। मेट्रोलाइट रेल का निर्माण सामान्य मेट्रो की 40 प्रतिशत लागत पर किया जाएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि मेट्रोनिओ का निर्माण उन शहरों में किया जा रहा है, जहां यात्रियों की संख्या कम है। इस मेट्रो का निर्माण सामान्य मेट्रो की 25 प्रतिशत लागत पर हो जाएगा। इसी प्रकार, वाटर मेट्रो अलग सोच वाली होगी। इसका निर्माण उन शहरों में किया जा रहा है, जहां बड़े-बड़े जल निकाय हैं। यह द्वीपों के पास रहने वाले लोगों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।

श्री मोदी ने कहा कि बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल की उपलब्धि से हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्रेकिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ब्रेक लगाने पर 50 प्रतिशत ऊर्जा वापस ग्रिड में चली जाती है। आज दिल्ली मेट्रो में 130 मेगावाट सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 600 मेगावाट कर दिया जाएगा। ■

किसानों की आय बढ़ाने में 'किसान रेल सेवा' एक बड़ा कदम: नरेन्द्र मोदी

किसान रेल के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई में कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। इससे छोटे से छोटा उत्पादक भी कम लागत में बड़े बाजारों तक पहुंच सकता है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा देश के किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच 4 महीनों में 100वीं किसान रेल चलाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि यह सेवा कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आएगी और देश की कोल्ड सप्लाई चेन को सशक्त करेगी। उन्होंने आगे कहा कि किसान रेल के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई में कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। यहां तक कि इससे छोटे से छोटा उत्पादक भी कम लागत में बड़े बाजारों तक उपयुक्त ढंग से पहुंच सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल परियोजना न सिर्फ किसानों को सेवा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे हमारे किसान नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तेजी से तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब अपने उत्पाद न सिर्फ अपने राज्य में बेच सकते हैं, बल्कि किसान रेल और कृषि उड़ान सेवाओं के माध्यम से भी अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं, जिनकी कृषि क्षेत्र में बड़ी भूमिका होगी।

श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल सचल शीत गृह (मोबाइल कोल्ड स्टोरेज) की व्यवस्था है जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाती है वह भी पूर्ण सुरक्षा के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूं तो भारत के पास आजादी के पहले से भी रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, कोल्ड स्टोरेज तकनीक भी पहले से थी, लेकिन किसान रेल के माध्यम से इस समय इसे सशक्त बनाया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल जैसी सुविधाओं ने पश्चिम बंगाल के लाखों किसानों को एक बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सुविधा किसानों के साथ-साथ स्थानीय छोटे व्यवसायियों के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में मौजूद विशेषज्ञों और दुनिया के अन्य देशों के अनुभवों तथा नई प्रौद्योगिकियों का भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रियान्वयन हो रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि जल्द खराब होने वाले 'कृषि उत्पादों का भंडारण केंद्र' रेलवे स्टेशनों के आसपास निर्मित किए जा रहे हैं, जहां किसान अपने उत्पादों का संग्रहण कर सकते हैं। यह प्रयास ज्यादा से ज्यादा संख्या में फलों और सब्जियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के क्रम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यकता से अधिक उत्पाद होने की स्थिति में जूस, आचार, चिप्स इत्यादि को छोटे निर्माताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए।

- **हाल के कृषि सुधारों से कृषि व्यवसाय और इन समूहों को व्यापक पैमाने पर लाभ पहुंचेगा और इन्हें बड़ा विस्तार मिलेगा**

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि सरकार की प्राथमिकता संग्रहण से जुड़े ढांचे के निर्माण और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन संबंधित प्रसंस्करण उद्योग से हैं। उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजनाओं के अंतर्गत 6500 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत स्वीकृति दे दी गई है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है।

श्री मोदी ने कहा कि हाल के कृषि सुधारों से कृषि व्यवसाय और इन समूहों को व्यापक पैमाने पर लाभ पहुंचेगा और इन्हें बड़ा विस्तार मिलेगा। इन समूहों को मदद करने के सरकार के प्रयास में निजी निवेश से सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कृषि और किसानों को सशक्त करने के मार्ग पर हम पूर्ण समर्पण भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। ■

सरकार ने सभी फसलों के लिए 40-70 प्रतिशत तक बढ़ाई एमएसपी

एमएसपी में खरीद का खर्च 2009-14 से 2014-19 में 85 प्रतिशत बढ़ा है। कुछ वर्षों में कृषि विभाग का बजट छह गुना बढ़ गया है

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने 30 दिसंबर को कहा कि सरकार ने न केवल उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाने की स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया, बल्कि सभी फसलों के लिए एमएसपी को 40-70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। एमएसपी में खरीद का खर्च 2009-14 से 2014-19 में 85 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में कृषि विभाग का बजट छह गुना बढ़ गया है।

श्री पुरी ने बताया कि एमएसपी एक प्रशासनिक व्यवस्था है और कानून विशेष रूप से हमारे किसानों के लिए कई परतों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कॉर्पोरेट्स के किसी भी अनुचित दावों से निपटने के लिए कानूनी सुरक्षा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे किसानों की जमीन का अधिग्रहण या पट्टे पर लेने की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि हमारे किसान जमीन, मिट्टी और जंगलों के मालिक हैं और जमीन वास्तव में उनकी मां की तरह है। उन्होंने इसकी देखभाल के लिए अपना जीवन, खून और पसीना समर्पित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी को भी उनकी जमीन लेने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अमूल को-ऑपरेटिव सफलता ने दिखाया है कि अलग-अलग छोटे पैमाने पर उत्पादन की प्रणाली जो किसी भी क्षेत्र में मौजूद हो सकती है, के बावजूद लोग साथ मिलकर सफलता की कहानी लिख सकते हैं।

श्री पुरी ने आगे कहा कि आज अमूल केवल दूध का उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि इसका अधिकांश राजस्व दुनियाभर में निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से आता है। कुछ इसी तरह की सफलता की कहानी हम इन सुधारों के माध्यम से हमारे किसानों के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं जो छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाते हैं और उन्हें सामाजिक पूंजी, सूचनाओं तक पहुंच के साथ ही खरीद फरोख्त की ताकत प्रदान करते हैं। श्री पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र से बंगाल तक चलने वाली 100वीं किसान रेल का शुभारंभ किया है, जिससे किसान अपनी 50-100 किलोग्राम उपज को कोल्ड चेन कोचों में भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है ताकि गोदाम, कोल्ड स्टोर, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और

पैकेजिंग यूनिट्स, ग्रामीण मार्केटिंग मंच, ई-मार्केटिंग यूनिट आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी उपलब्ध हो। किसान सम्मान निधि (1,10,000 करोड़ रुपये पहले ही इसके तहत भुगतान किए जा चुके हैं) हमारे किसानों की मदद करती है और उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए गुजर-बसर के मसलों को कम करती है, जो हमारे छोटे और सीमांत किसानों के लिए गंभीर संकट का कारण बनते थे। उन्होंने आगे कहा कि फसल बीमा व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना ने 17,450 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले किसानों को बीमा के रूप में 87,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। श्री पुरी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है और हमारी लगभग 70 प्रतिशत एमएसपी खरीद इन राज्यों से होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि 52.5 प्रतिशत कृषक परिवार औसतन 1,470 डॉलर के कर्जदार थे। उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत पैदा की गईं फसलें उचित कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा, कई बिचौलियों के कारण कृषि क्षेत्र काफी खंडित है और उनके पास भारी लाभ पहुंचता है।

- **पंजाब और हरियाणा की राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है और हमारी लगभग 70 प्रतिशत एमएसपी खरीद इन राज्यों से होती है**

श्री पुरी ने कहा कि हमारे मेहनती किसान हमारे कृषि प्रधान राज्यों को दुनिया के अन्न भंडार में बदल सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि कृषि सुधार कानून बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर किसानों की मदद करने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ■

प्रधानमंत्री ने छह राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत छह राज्यों में छह स्थानों पर 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे।

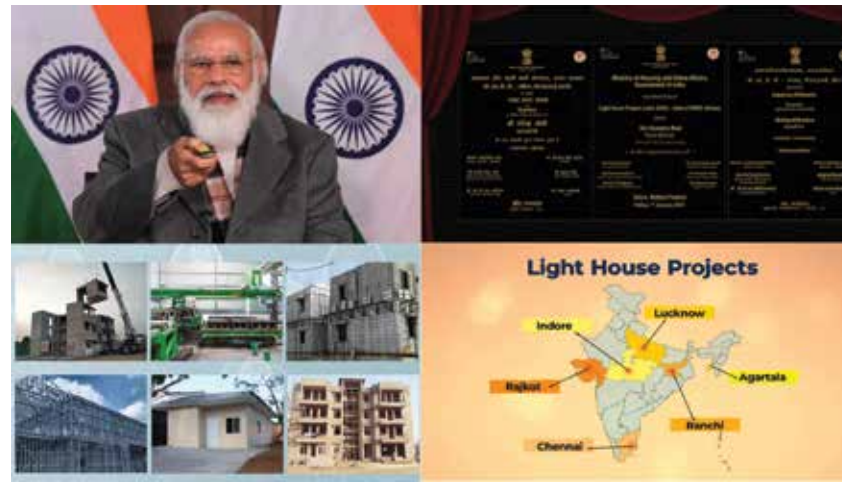

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने, नए संकल्पों को साबित करने का दिन है और आज देश को गरीब, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई तकनीक मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन घरों को तकनीकी भाषा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन ये 6 परियोजनाएं वास्तव में लाइट हाउस की तरह हैं जो देश में आवास निर्माण के क्षेत्र को एक नई दिशा दिखा रही है।

श्री मोदी ने इन लाइट हाउस परियोजनाओं को वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एक समय में आवास योजनाएं केन्द्र सरकार की प्राथमिकता नहीं हुआ करती थीं, गृह निर्माण की बारीकियां और गुणवत्ता भी नहीं थी। आज, देश ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक अलग मार्ग और बेहतर तकनीक को अपनाते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

• आज, देश ने परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक अलग मार्ग और बेहतर तकनीक को अपनाते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाया है

श्री मोदी ने सरकारी मंत्रालयों के लिए बड़े और निष्क्रिय ढांचे की नहीं, बल्कि स्टार्टअप की तरह फिट होने वाले ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर से 50 से अधिक उन्नतिशील निर्माण कंपनियों की सक्रिय भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक चुनौती ने हमें नई तकनीक के साथ नया करने और विकास को बढ़ावा देने का अवसर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रक्रिया के अगले चरण में विभिन्न स्थानों पर 6 लाइट हाउस परियोजनाओं का काम आज से शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और नवीन प्रक्रियाओं से बने होंगे और निर्माण के समय को कम करेंगे और गरीबों के लिए अधिक लचीले, किफायती और आरामदायक घर बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन लाइट हाउसों में निर्माण प्रौद्योगिकी में नवाचार हैं। उदाहरण के लिए इंदौर में परियोजना में ईंट और मोर्टार दीवारें नहीं होंगी, इसके बजाय वे पूर्वनिर्मित सैंडविच पैनल प्रणाली का उपयोग करेंगे। राजकोट में लाइट हाउसों को फ्रेंच तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा और सुरंग का उपयोग करके एक पत्थर की ठोस निर्माण तकनीक होगी। ये घर आपदाओं को झेलने में अधिक समर्थ होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि चेन्नई में यूएस और फिनलैंड की प्रौद्योगिकियां प्रीकास्ट कंक्रीट प्रणाली का उपयोग करेंगी, जिससे घर का निर्माण तेजी से और सस्ता होगा। जर्मनी की 3 डी निर्माण प्रणाली का उपयोग करके रांची में मकान बनाए जाएंगे। प्रत्येक कमरे को अलग से बनाया जाएगा और फिर पूरी संरचना को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगरतला में स्टील के फ्रेमों के साथ न्यूजीलैंड की तकनीक का उपयोग करते हुए मकान बनाए जा रहे हैं जो भूकंप के बड़े जोखिम को झेल सकते हैं। कनाडा की प्रौद्योगिकी का उपयोग लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टर और पेंट की आवश्यकता नहीं होगी और तेजी से मकान बनाने के लिए पहले से तैयार की गई पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा।

श्री मोदी ने आगे कहा कि प्रत्येक स्थान पर 12 महीनों में हजारों घर बनाए जाएंगे जो इंक्यूबेशन केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे योजनाकार, वास्तुकार, इंजीनियर और छात्र नई तकनीक के साथ अध्ययन और प्रयोग कर सकेंगे। ■

भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल का लें संकल्प: नरेन्द्र मोदी

जो भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है। स्टार्टअप को भी आगे आना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसंबर को देशवासियों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले विदेश में निर्मित वस्तुओं के विकल्प के रूप में मौजूद भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील की और कहा कि उन्हें देश के लिए इसे नव वर्ष के संकल्प के तौर पर लेना चाहिए।

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 72वें और वर्ष 2020 के आखिरी संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को देश की जनता ने हाथों-हाथ लिया है।

इस अवसर पर उन्होंने निर्माताओं तथा उद्योग जगत से विश्वस्तरीय उत्पाद बनाना सुनिश्चित कर 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया।

'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को लेकर नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' आज घर-घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय हों। उन्होंने कहा कि लोग अब भारत में बने उत्पादों की मांग कर रहे हैं और यहां तक कि दुकानदार भी भारत में बने उत्पादों को बेचने पर जोर दे रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वह भी एक साल के भीतर-भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तौल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हर नए साल में देशवासी कोई न कोई संकल्प लेते हैं और इस बार भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल करने का संकल्प लें।

• वोकल फॉर लोकल आज घर-घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय हों

श्री मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि दिनभर इस्तेमाल होने वाली चीजों की आप एक सूची बनाएं। उन सभी चीजों की विवेचना करें और यह देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है तथा एक प्रकार से हमें बंदी बना दिया है। भारत में बने इनके विकल्पों का पता करें और यह भी तय करें कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लोगों ने मजबूत कदम आगे बढ़ाया है और निर्माताओं तथा उद्योग जगत के लिए 'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' की सोच के साथ काम करने का उचित समय है। उन्होंने कहा कि जो भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है। स्टार्टअप को भी आगे आना है।

उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को बनाए रखने, बचाए रखने और बढ़ाते रहने का देशवासियों से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कश्मीरी 'केसर' को मिले जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) का जिक्र किया और कहा कि इस नई पहचान के बाद केंद्र सरकार इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय ब्रांड बनाने की मंशा रखती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब कश्मीरी केसर का निर्यात बढ़ेगा तथा इससे 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

मई महीने में कश्मीरी केसर को मिले जीआई टैग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का केसर बहुत विशिष्ट है और दूसरे देशों के केसर से बिलकुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग से एक अलग पहचान मिली है। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक वैश्विक लोकप्रिय ब्रांड बनाना चाहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि केसर जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और यह सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है जो मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग की पहचान मिलने के बाद दुबई के एक सुपर मार्केट में इसे लांच किया गया। उन्होंने कहा कि अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए देशवासियों से कूड़ा-कचरा न फैलाने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया और एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से देश को मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में साठ प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे देश के लिए 'बड़ी' उपलब्धि करार दिया।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी के दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेहसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनको इसी दिन दीवार पर जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गयी शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को, नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। ■

मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण

वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी की सर्वाधिक स्वीकृति

कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दुनियाभर में लोकप्रियता में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। विश्व के नेताओं की उनके कार्यकाल में स्वीकृति पर नजर रखने वाली डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक श्री नरेन्द्र मोदी विश्व नेताओं में शीर्ष पर हैं।

मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह भी दिखाया गया है कि श्री मोदी की लोकप्रियता सभी वैश्विक नेताओं में सबसे अधिक है। यह एजेंसी दुनिया भर के नेताओं और सरकार की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 75 फीसदी लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का समर्थन किया, वहीं 20 फीसदी ने उन्हें स्वीकार्य नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55 रही है, जो दुनिया के नेताओं में सबसे अधिक है। इसके अलावा जर्मनी की चांसलर सुश्री एंजेला मर्केल की स्वीकृति रेटिंग 24 प्रतिशत रही। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन की स्वीकृत रेटिंग नकारात्मक रही है, जिसका मतलब है कि उनका समर्थन करने वालों के मुकाबले विरोध करने वालों की संख्या अधिक है। ■

जगत प्रकाश नड्डा
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता निर्विवाद रूप से न सिर्फ सभी भौगोलिक क्षेत्रों और जनसांख्यिकीय समूहों में बढ़ी है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के चलते उन्हें वैश्विक स्वीकृति भी मिली है। चुनौतियों से भरे इस समय में प्रधानमंत्री मोदी जी सभी वैश्विक नेताओं में शीर्ष पर हैं।"

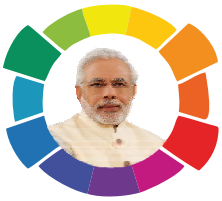

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

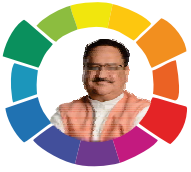

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल के शुभारंभ अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आईआईएम संबलपुर (ओडिशा) के स्थायी कैम्पस की आधारशिला रखने के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत 'पीएम-जय सेहत' के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

छायाकार: अजय कुमार सिंह